GUPTA CLASSES

करेंट अफेयर्स

जनवरी-2022

हिन्दी

भाग-2

GUPTA CLASSES

GOVT SCHEMES

CENTRAL GOVT SCHEMES

PM मोदी ने एक नई रूफटॉप सोलर ऊर्जा योजना 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' लॉन्च की

22 जनवरी 2024 को, प्रधान मंत्री (**PM**) नरेंद्र मोदी ने **1 करोड़ घरों** को रूफटॉप सोलर (**RTS**) पावर सिस्टम प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना "**प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना**" शुरू की।
यह योजना भारत को 40 गीगावाट (GW) रूफटॉप सोलर कैपेसिटी का लक्ष्य हासिल करने में सहायता करेगी।

योजना के बारे में:

i.उद्देश्य: रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन के माध्यम से बिजली प्रदान करना, साथ ही अधिशेष बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय की पेशकश करना।
ii.यह योजना गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों को उनके बिजली बिल कम करने में सहायता करने के लिए है।

पृष्ठभूमि:

i.2014 में, सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम शुरू किया, जिसका उद्देश्य केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके आवासीय क्षेत्रों में भारत की RTS कैपेसिटी का विस्तार करना है।
ii.यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र प्रोजेक्ट्स को प्रदान किया जाएगा, और DISCOM को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
iii.प्रोग्राम में 2022 तक 40,000 मेगावाट (MW) या 40 GW की क्युमुलेटिव इन्सटाल्ड कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी गई थी।
अतिरिक्त जानकारी: DISCOM(वितरण कंपनियों) से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद प्रोजेक्ट डेवलपर्स/सिस्टम इंटीग्रेटर्स/मनुफेक्टर्स आदि के माध्यम से RTS सिस्टम का लाभ उठाया जा सकता है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम का कार्यकाल आंशिक संशोधन के साथ 1 वर्ष तक बढ़ाया गया

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को आंशिक संशोधनों के साथ एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह अमेंडेड इंसेंटिव स्कीम 2023-24 (FY24) से शुरू होकर 2027-28 (FY28) तक लगातार पांच वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगी।

- यह निर्णय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) की मंजूरी मिलने के बाद किया गया है।
- इन संशोधनों का उद्देश्य स्कीम को स्पष्टता और लचीलापन प्रदान करना है।

अमेंडेड स्कीम क्या है?

i.इसके तहत, इंसेंटिव डिस्बर्समेंट अगले वित्तीय वर्ष यानी FY25 में किया जाएगा।
ii.यदि कोई कंपनी एक वर्ष में निर्धारित बिक्री मूल्य सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेगा।
iii.अगले वर्ष में लाभ के लिए पात्रता यदि सीमा को 10% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ पूरा किया जाता है।

पृष्ठभूमि:

PLI-ऑटो स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को 5 वर्ष की अवधि (FY2022-23 से FY2026-27) के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। PLI-ऑटो स्कीम **एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी** (AAT) उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देगी।

- यह स्कीम प्रमाणित न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन के साथ AAT उत्पादों का समर्थन करती है।

MNRE ने PVTG क्षेत्रों में घरों के विद्युतीकरण के लिए 515 करोड़ रुपये की सौर योजना शुरू की

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय **(MNRE)** ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों **(PVTG)** की बस्तियों और गांवों में विद्युतीकरण के लिए **515 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ **'नई सौर ऊर्जा योजना'** शुरू की है।

- यह योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान **(PM-JANMAN)** कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी।
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 **(FY24)** से वित्तीय वर्ष 2025-26 **(FY26)** तक विस्तारित अवधि के लिए शुरू की गई है।

नई सौर ऊर्जा योजना:

i.इस योजना का लक्ष्य भारत भर के 18 राज्यों और अंडमान & निकोबार के केंद्र शासित प्रदेशों (**UT**) में जनजातीय मामलों के मंत्रालय (**MoTA**) द्वारा पहचाने गए एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों में सौर ऊर्जा प्रदान करना है।

- 18 राज्य - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल हैं ।

ii.योजना ने उन स्थानों पर 0.3 किलोवाट (kW) **ऑफ-ग्रिड** सौर प्रणाली के लिए प्रावधान किया है जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

iii.यह योजना PVTG क्षेत्रों में 15 करोड़ की लागत से 1,500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (**MPC**) में सौर प्रकाश व्यवस्था भी प्रदान करती है जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली संभव नहीं है।

iv.योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि MNRE की अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (**DAPST**) द्वारा प्रदान की जाएगी।

निधि वितरण:

आवंटित निधि में से, FY24 में 20 करोड़ रुपये, FY25 में 255 करोड़ रुपये और FY26 में 240 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। 515 करोड़ रुपये में से 500 करोड़ रुपये का उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में घरों के विद्युतीकरण के लिए किया जाएगा, जिसमें एक लाख PVTG घरों के लिए 0.3 kW सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली की स्थापना शामिल है।

- योजना के दूसरे घटक के लिए, सरकार **15 करोड़ रुपये** की लागत से आदिवासी क्षेत्रों में 1,500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (MPC) में सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रदान करेगी।

PM-JANMAN:

i.यह योजना नवंबर 2023 में MoTA को नोडल एजेंसी बनाकर शुरू की गई थी।

ii.योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचना है।

iii.यह योजना नौ मंत्रालयों (MNRE सहित) में 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों/महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अतिरिक्त जानकारी:

i.घरों के विद्युतीकरण के लिए, सरकार प्रति घर 50,000 रुपये या वास्तविक लागत प्रदान करती है।

ii.सौर प्रकाश व्यवस्था के लिए, सरकार प्रति MPC 1 लाख रुपये प्रदान करेगी।

STATE GOVT SCHEMES

असम के CM ने SGH की महिलाओं की सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान' योजना का अनावरण किया

असम के मुख्यमंत्री (CM) **हिमंत बिस्वा सरमा** ने 4 मिलियन स्व-सहायता-समूह (SHG) महिलाओं को ग्रामीण **सूक्ष्म-उद्यमियों** के रूप में विकसित करने और उन्हें 'लखपति बैदोस (बड़ी बहन) बनने में मदद करने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान' योजना शुरू की। '.

- योजना का परिव्यय **4,000 करोड़ रुपये** है और इसे SHG सदस्यों को पेश किया जाएगा जो अपनी समूह गतिविधि के साथ-साथ व्यक्तिगत व्यवसाय योजना के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के बारे में:

i.योजना के तहत, पात्र महिलाओं को तीन वर्षों में 35,000 रुपये मिलते हैं।

- **चरण I -** प्रत्येक पात्र महिला को पहले वर्ष में 10,000 रुपये (उद्यमिता निधि) मिलेंगे।
- **चरण II** - अगले दो वर्षों में SHG सदस्यों को **बैंक** से 25,000 रुपये की ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
- 25,000 रुपये को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें 12,500 रुपये सरकार का पैसा (पूंजी सब्सिडी, गैर-वापसी योग्य) और 12,500 रुपये बैंक का चुकाना होगा।

ii.अनुदान तक पहुंचने के लिए, लाभार्थियों को सरकार समर्थित व्यवसाय योजना की आवश्यकता होती है।

iii.योजना के लाभार्थियों को कुछ सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को पूरा करना होगा।

- इन मानदंडों में शामिल है कि सामान्य और OBC श्रेणियों की महिलाओं के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के चार से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
- जिन SHG सदस्यों के पास लड़कियाँ हैं उन्हें उन्हें स्कूल में नामांकित करना होगा या छोटे बच्चों के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।

विशेष रूप से, असम राज्य की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक नीति का पालन कर रहा है, और उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जनसंख्या नियंत्रण उपायों से जोड़ा जाएगा।

असम के बारे में:

राज्यपाल– गुलाब चंद कटारिया

राष्ट्रीय उद्यान- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभ्यारण्य- गरमपानी वन्यजीव अभ्यारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य

19 जनवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु दौरा की मुख्य विशेषताएं

प्रधान मंत्री (PM) श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया और विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया

i.महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की 8 AMRUT प्रोजेक्ट्स

ii.संयुक्त राज्य के बाहर बेंगलुरु में बोइंग की सबसे बड़ी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा

iii.चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन समारोह

iv.दूरदर्शन चैनल DD पोधिगई के संशोधित संस्करण को 'DD तमिल' के रूप में लॉन्च किया गया।

महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की 8 AMRUT प्रोजेक्ट्स

महाराष्ट्र की दौरा के दौरान, प्रधान मंत्री ने लगभग **2000 करोड़ रुपये** की 8 AMRUT (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन) प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। उन्होंने भी

- PMAY-शहरी के तहत पूर्ण किए गए 90000 से अधिक घर समर्पित किया
- सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15000 घर समर्पित किए, जिनमें लाभार्थियों के रूप में हथकरघा श्रमिक, विक्रेता, पावरलूम श्रमिक, कचरा बीनने वाले, बीड़ी श्रमिक और ड्राइवर शामिल थे।
- महाराष्ट्र में PM-SVANIDHI के 10000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त का वितरण शुरू किया गया

नोट:

योजना	उद्देश्य	में शुरू किया था	मंत्रालय
AMRUT (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन)	हर किसी के पास नल के पानी और सीवरेज सुविधाओं तक पहुंच है, पार्क और खुली जगहों जैसी हरियाली अच्छी तरह से बनाए रखी गई है, डिजिटल और स्मार्ट सुविधाएं जैसे मौसम की भविष्यवाणी, इंटरनेट और WiFi सुविधाएं, जनता को सस्ते लेकिन सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का	जून 2015 • राज्य वार्षिक कार्य योजना AMRUT प्रस्तुत करने वाला पहला	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

	उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके प्रदूषण में कमी आदि ह।	राज्य राजस्थान था	
PMAY-शहरी (प्रधानमंत्री आवास योजना)	शहरी क्षेत्रों के निम्न और मध्यम आय वाले निवासियों के लिए किफायती आवास तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना	जून 2015	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
PM-SVANIDHI (PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि)	i.पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर, दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के बढ़े हुए ऋण के साथ, 1 वर्ष की अवधि के 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करें। ii.प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करें iii.प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करें।	1 जून 2020	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

बेंगलुरु में संयुक्त राज्य के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा का उद्घाटन

i.PM ने 43 एकड़ भूमि पर **1600 करोड़ रुपये** के निवेश के साथ बेंगलुरु, कर्नाटक में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग & टेक्नोलॉजी सेंटर (BIETC) परिसर का उद्घाटन किया।

- यह भारत में वाइब्रेंट स्टार्टअप, निजी और सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देगा
- और वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा

ii.PM ने **बोइंग सुकन्या कार्यक्रम** भी लॉन्च किया जिसका उद्देश्य पूरे भारत से अधिक लड़कियों को देश के विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना है।

- यह कार्यक्रम युवा लड़कियों के लिए STEM करियर में रुचि जगाने में मदद करने के लिए 150 नियोजित स्थानों पर STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) प्रयोगशालाएं बनाएगा।
- और पायलट बनने का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा

चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन समारोह

PM मोदी तमिलनाडु के चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) 2023 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह पहली बार है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किए जा रहे हैं।

- KIYG 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के चार शहरों- चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयंबटूर में आयोजित किया जाएगा।

- गेम्स की शुभंकर **वीरा मंगई** है जो **रानी वेलु नचियार** से प्रेरित है जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था।
- गेम्स के लोगो में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति शामिल है।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में 5600 से अधिक एथलीट 15 स्थानों पर 26 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स, 275 से अधिक कॉम्पिटिटिव इवेंट्स और 1 डेमो स्पोर्ट के साथ भाग लेंगे।
- तमिलनाडु के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स **सिलंबम** को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार डेमो स्पोर्ट्स के रूप में पेश किया जा रहा है।
- 26 खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि जैसे कन्वेंशनल स्पोर्ट्स और कलारीपयट्टू, गतका, थांग ता, कबड्डी और योगासन जैसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शामिल हैं।

दूरदर्शन चैनल DD पोधिगई का एक संशोधित संस्करण 'DD तमिल' के रूप में लॉन्च किया गया

KIYG 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान, PM ने **250 करोड़ रुपये** की प्रसारण क्षेत्र से संबंधित प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया।

- इसमें DD तमिल के रूप में संशोधित DD पोधिगई चैनल का लॉन्च शामिल था
- 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी FM प्रोजेक्ट्स
- जम्मू और कश्मीर में 4 DD ट्रांसमीटर
- इसके अलावा PM 12 राज्यों में 26 नए FM ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे

नोट: DD पोधिगई भारत में अपना HD संस्करण लॉन्च करने वाला पहला दूरदर्शन टेलीविजन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1975 को हुई थी

PM का 16-17 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा

PM ने 16-17 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा किया। राज्य की अपनी दौरा के दौरान उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया जो हैं:

i.कोच्चि, केरल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स

ii.आंध्र प्रदेश के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और मादक पदार्थ अकादमी का नया परिसर

कोच्चि, केरल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स

PM ने भारत के बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने और इसमें क्षमता और आत्मनिर्भरता बनाने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप 4000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं

i.कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में नया ड्राई डॉक (NDD)

यह प्रोजेक्ट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मौजूदा परिसर में 1800 करोड़ रुपये में बनाई गई है और यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है।

- इसकी लंबाई 310 मीटर, चौड़ाई 75/60 मीटर और गहराई 13 मीटर है
- इसमें 9.5 मीटर तक का ड्राफ्ट (यह बताता है कि जहाज पानी में कितना गहरा है) है
- यह 70000MT विस्थापन तक के भविष्य के विमान वाहक और बड़े वाणिज्यिक जहाजों जैसी रणनीतिक संपत्तियों को संभाल सकता है

ii.CSL की अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा (ISRF)

ISRF 970 करोड़ रुपये में बनाया गया है जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) की मौजूदा जहाज मरम्मत क्षमताओं में सुधार करके इसे वैश्विक जहाज मरम्मत केंद्र में बदल देगा। ISRF के पास

- 6000 T की क्षमता वाला जहाज उठाना प्रणाली
- स्थानांतरण प्रणाली
- 6 कार्यस्थान

- और लगभग 1400 मीटर की बर्थ जिसमें 130 मीटर लंबाई के 7 जहाज एक साथ रह सकते हैं

iii.पुथुवाइपीन, कोच्चि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का LPG इम्पोर्ट टर्मिनल

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) का LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) टर्मिनल सभी के लिए सुलभ & सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत के प्रयासों को मजबूत करने के लिए 1236 करोड़ रुपये में बनाया गया है

- इसकी भंडारण क्षमता 15400 MT है

पलासमुद्रम, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर & मादक पदार्थ अकादमी का नया परिसर

i.PM ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और मादक पदार्थ अकादमी (NACIN) के नए अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया।

- यह 500 एकड़ में फैला हुआ है
- यह भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क & अप्रत्यक्ष कर) के अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय संबद्ध सेवाओं, राज्य सरकारों & भागीदार देशों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है।
- परिसर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ऑगमेंटेड & वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा।

ii.उन्होंने **'फ्लोरा ऑफ पलासमुद्र'** नामक पुस्तक का भी विमोचन किया।

- पलासमुद्रम गाँव भारत के आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के पलासमुद्रम मंडल में स्थित है

नोट: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2014 में राज्य के लिए अकादमी को मंजूरी दी गई थी। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने **11 अप्रैल 2015** को अकादमी की आधारशिला रखी थी। NACIN का नया परिसर देश में दूसरा है

INTERNATIONAL AFFAIRS

2024 में पांच नए देश BRICS में शामिल होंगे

पांच देश अर्थात् मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात **(UAE) BRICS** (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) ब्लॉक में शामिल हो गए हैं क्योंकि उनकी सदस्यता 1 जनवरी, 2024 से लागू हो गई है।

- नए सदस्यों के शामिल होने के साथ, BRICS की सदस्यता संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई।

पृष्ठभूमि:

अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में 15वें BRICS शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

नोट: अर्जेंटीना जिसे BRICS में शामिल होना था, उसके राष्ट्रपति **जेवियर माइली** ने प्रवेश से नाम वापस ले लिया।

प्रमुख बिंदु:

i.नए सदस्यों को शामिल करने को पारंपरिक ग्लोबल व्यवस्था को एक बहुध्रुवीय दुनिया में फिर से आकार देने के एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जाता है, जिसमें ग्लोबल साउथ की आवाजें अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

ii.दो विशाल शक्तियों (सऊदी अरब और UAE) का समावेश स्थापित पश्चिमी नेतृत्व वाले आदेश को चुनौती देने वाली मध्य शक्तियों की बढ़ती मुखरता को उजागर करता है।

iii.BRICS का विस्तार सऊदी अरब और UAE में निवेश के नए अवसर भी पैदा करता है।

iv.दोनों देश पर्यटन, रियल एस्टेट, निर्माण, परिवहन, विनिर्माण और पूंजीगत व्यय सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता ला रहे हैं।

2024 BRICS अध्यक्षता:

i.1 जनवरी 2024 को रूस ने BRICS की अध्यक्षता संभाली है।

ii.रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने **"स्ट्रेंग्थेनिंग मल्टीलेटरलिस्म फॉर इक्वीटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी"** विषय के माध्यम से ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

iii.16वां BRICS शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में कज़ान, **रूस** में होने वाला था।

BRICS के बारे में:

i.BRICS का गठन सितंबर 2006 में हुआ था और इसमें मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन (BRIC) शामिल थे।

ii.सितंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर **BRICS** कर दिया गया।

iii.वर्तमान में, BRICS ग्लोबल आबादी का 41%, ग्लोबल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 24% और ग्लोबल व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है।

भारत जुलाई 2024 में UNESCO की विश्व विरासत समिति की अध्यक्षता & मेजबानी करेगा

भारत 21-31 जुलाई, 2024 तक नई दिल्ली, दिल्ली में **UNESCO** (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) **विश्व विरासत समिति** के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार है।

- यह भारत के लिए UNESCO विरासत समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने का पहला मौका है।

नोट: 19वें असाधारण सत्र के दौरान विश्व विरासत समिति ने निर्णय लिया कि 46वां सत्र भारत में होगा।

ब्यूरो सदस्य:

अध्यक्ष– विशाल V शर्मा (UNESCO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि)

प्रतिवेदक: श्री मार्टिन औक्लानी (बेल्जियम)

उपाध्यक्ष: बुल्गारिया, ग्रीस, केन्या, कतर, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस

प्रमुख बिंदु:

i.विश्व विरासत समिति विश्व विरासत सूची और खतरे में विश्व विरासत की सूची से समावेशन, परिवर्धन और निष्कासन का निर्धारण करती है।

ii.समिति की बैठक साल में एक बार होती है और इसमें 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

iii.UNESCO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

अतिरिक्त जानकारी:

UNESCO विश्व विरासत समिति के 45वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी सऊदी अरब ने रियाद में की।

अध्यक्ष- डॉ. अब्दुलेला अल-तोखैस

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) के बारे में:

UNESCO का संविधान 1945 में लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में अपनाया गया था, यह 1946 में लागू हुआ।

महानिदेशक– ऑड्रे अज़ोले

मुख्यालय– पेरिस, फ्रांस

इंदौर, भोपाल, उदयपुर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रिडिटेशन के लिए नामांकित किया गया

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (**MoEF&CC**) ने **रामसर कन्वेंशन** के तहत **वेटलैंड सिटी एक्रिडिटेशन (WCA)** योजना के लिए तीन भारतीय सिटीज अर्थात् मध्य प्रदेश (**MP**) के **इंदौर** और **भोपाल** और **राजस्थान** के **उदयपुर** को नामित किया है। ये WCA के लिए नामांकित होने वाले पहले तीन भारतीय सिटीज हैं।

WCA के बारे में:

WCA एक स्वैच्छिक एक्रिडिटेशन प्रणाली है जिसे संविदा दलों के सम्मेलन (COP) 12, 2015 के दौरान रामसर कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था।

i.उद्देश्य:

उन शहरों को पहचानना जिन्होंने अपने अर्बन वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं।

अर्बन और पेरी-अर्बन वेटलैंड्स के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के साथ-साथ स्थानीय आबादी के लिए स्थायी सामाजिक-आर्थिक लाभों को बढ़ावा देना।

ii.मानदंड: एक्रिडिटेशन प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को 6 इंटरनेशनल मानदंडों को पूरा करना होगा जिसमें इसके क्षेत्र में या इसके आसपास के क्षेत्र में रामसर स्थलों या अन्य महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की उपस्थिति शामिल है।

iii.एक्रिडिटेशन सिटीज: सम्मेलन ने COP13 के दौरान 18 शहरों और COP14 के दौरान 25 सिटीज को एक्रिडिटेशन दी है। इन 43 सिटीज में चीन के 13 और फ्रांस के 6 सिटीज शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.नामांकित भारतीय सिटीज में और उसके आसपास स्थित वेटलैंड्स हैं

इंदौर - सिरपुर वेटलैंड (रामसर स्थल); यशवन्त सागर (रामसर स्थल)

भोपाल- भोज वेटलैंड (रामसर स्थल),

उदयपुर - 5 प्रमुख वेटलैंड्स, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है।

ii.होल्कर राजवंश द्वारा स्थापित इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है और भारत के स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 का प्राप्तकर्ता है। भोपाल भारत का छठा सबसे स्वच्छ सिटी है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में:

रामसर कन्वेंशन (कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ़ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस) एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी, 1971 को ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर सिटी ऑफ़ रामसर में अपनाया गया था।

- यह भारत सहित अपने 172 सदस्य देशों में वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- वर्तमान में, भारत में 75 वेटलैंड्स संधि के तहत संरक्षित हैं।

महासचिव– डॉ. मुसोंडा मुंबा

मुख्यालय– ग्लैंड, स्विट्जरलैंड

IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर स्थापित करेगा

तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT-मद्रास) 2024 में श्रीलंका के कैंडी में अपनी टेक यूनिवर्सिटी का एक नया परिसर शुरू करने के लिए तैयार है।

श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉ. सुशील प्रेमजयंता ने घोषणा की कि यह प्रस्ताव वित्त मंत्री के रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 का हिस्सा था।

- जनवरी 2024 में, IIT-मद्रास के अधिकारी श्रीलंका में अपने परिसर की एक शाखा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए श्रीलंका का दौरा करेंगे।
- इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कैंपस शाखा की स्थापना प्रक्रिया शुरू करना शामिल है।
- उम्मीद है कि इस परिसर से श्रीलंकाई छात्रों को स्थानीय स्तर पर किफायती मूल्य पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

WHO ने ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा मापांक 2 लॉन्च किया; आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रणालियों को एकीकृत किया

10 जनवरी, 2024 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) ने नई दिल्ली, दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (**ICD-11**), पारंपरिक चिकित्सा (TM) अध्याय मापांक 2 लॉन्च किया।

i.ICD 11 TM मापांक 2 में **आयुर्वेद, सिद्ध** और **यूनानी** (ASU) प्रणालियों पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली शामिल है।

ii.इसके साथ, इन पारंपरिक प्रणालियों में बीमारियों को परिभाषित करने वाले शब्दों को रुग्णता कोड के रूप में अनुक्रमित किया जाता है और WHO रोग वर्गीकरण श्रृंखला ICD-11 में शामिल किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

i.मापांक के अंतिम मसौदे में 18 अध्यायों में वितरित कुल 529 कोड शामिल हैं।

ii.इस मापांक में 2 अलग-अलग प्रकार की शब्दावली या शीर्ष-लेवलीय ब्लॉक, अर्थात् पारंपरिक चिकित्सा विकार और पारंपरिक चिकित्सा नमूना शामिल हैं।

iii.यह बीमारियों को परिभाषित करने वाली शब्दावली के कोड के रूप में ASU चिकित्सा में वैश्विक एकरूपता सुनिश्चित करेगा।

iv.पारंपरिक औषधीय रोग, जिनमें मलेरिया जैसे संक्रामक रोग और पुरानी अनिद्रा जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियाँ शामिल हैं, इस वर्गीकरण में शामिल हैं।

AYUSH मंत्रालय & WHO के बीच सहयोग:

i.आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (**AYUSH**) मंत्रालय ने WHO के सहयोग से ICD-11 श्रृंखला के TM-2 मापांक के तहत ASU प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली बीमारियों का एक वर्गीकरण तैयार किया है।

ii.इस वर्गीकरण पहल के लिए WHO और AYUSH मंत्रालय के बीच एक दाता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

iii.इस सहयोग का उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, अनुसंधान, आयुष बीमा कवरेज, अनुसंधान & विकास और नीति निर्माण को मजबूत करना है।

iv.AYUSH मंत्रालय ने पहले ही राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल **(NAMSTE)** के माध्यम से ASU चिकित्सा के लिए कोड विकसित कर लिया है।

- इसके अलावा, इन कोडों का उपयोग समाज में विभिन्न बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की रणनीतियों के निर्माण में भी किया जा सकता है।

ICD-11 के बारे में:

ICD 11, ICD का **11वां संशोधन** है जिसने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और मृत्यु के कारणों को दर्ज करने के लिए वैश्विक मानक के रूप में ICD 10 को प्रतिस्थापित कर दिया है। इसे WHO द्वारा प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है।

ICD-11 को 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया और 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ।

अतिरिक्त जानकारी: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो (CBHI), ICD से संबंधित गतिविधियों के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में कार्य करता है। CBHI बीमारियों और मृत्यु दर के लिए डेटा संग्रह और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।

NITI आयोग & WFP ने एशिया & अफ्रीका में मिलेट को मुख्यधारा में लाने पर एक सारसंग्रह लॉन्च किया

12 जनवरी 2024 को, NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) ने नई दिल्ली में भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मिलेट के उपयोग को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का एक संग्रह लॉन्च किया।

यह लॉन्च एशिया और अफ्रीका में मिलेट मुख्यधारा के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज (MEGP) पहल के सफल समापन का भी प्रतीक है।

नोट: MEGP, जुलाई 2022 में शुरू हुआ, NITI आयोग और WFP की एक संयुक्त पहल है।

सारसंग्रह के बारे में:

i.यह सारसंग्रह क्षमता निर्माण और दुनिया भर में मिलेट अपनाने में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है।

ii.यह देशों को मिलेट जैसी जलवायु-लचीली फसलों में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

iii.यह मिलेट को मुख्यधारा की खाद्य प्रणालियों में एकीकृत करने के लिए एक संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा।

iv.यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग और नीति संवादों के माध्यम से सूचित निर्णय लेने और ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है।

v.यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के दौरान जलवायु लचीलापन, फूड सिक्योरिटी और छोटे किसानों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका के लिए मिलेट को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया।

उपस्थितगण:

इस कार्यक्रम में NITI आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, WFP, भारत की कंट्री निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

अतिरिक्त जानकारी:

i.संयुक्त राष्ट्र (UN) ने **2023** को **इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स (IYM)** घोषित किया है।

ii.मिलेट्स अनाज का एक समूह है जो पोएसी परिवार से संबंधित है, जिसे आमतौर पर घास परिवार के रूप में जाना जाता है। पूरे अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में इनका व्यापक रूप से सेवन किया जाता है

iii.2023 में, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज (MoFPI) ने **800 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ 2022-23 से 2026-27 के दौरान प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट-बेस्ड प्रोडक्ट्स (PLISMBP) लागू की है।

iv.भारत के मिलेट के कुल उत्पादन में **पर्ल मिलेट** (मिलेट), **सोरघम** (ज्वार) और **फिंगर मिलेट** (रागी) की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है।

WHO द्वारा काबो वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया

विश्व स्वास्थ्य संगठन **(WHO)** ने **काबो वर्डे गणराज्य** (जिसे काबो वर्डे या केप वर्डे के नाम से भी जाना जाता है) को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है।

- इसके साथ काबो वर्डे 1973 में **मॉरीशस** और 2019 में **अल्जीरिया** के बाद WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रमाणित होने वाला **तीसरा देश** बन गया।
- आज तक, WHO ने 43 देशों और 1 क्षेत्र को 'मलेरिया-मुक्त' प्रमाणन प्रदान किया है।

- WHO किसी देश को मलेरिया मुक्त तब प्रमाणित करता है जब वह देश भर में **लगातार 3 वर्षों** तक मलेरिया संचरण में रुकावट दर्शाता है।

काबो वर्डे गणराज्य के बारे में:

राष्ट्रपति – जोस मारिया नेवेस

राजधानी – प्रिया

मुद्रा - केप वर्डीन एस्कुडो

VISITS

INDIAN VISITS

2 और 3 जनवरी 2024 को PM मोदी की तमिलनाडु, लक्षद्वीप & केरल की यात्रा का अवलोकन

प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 जनवरी 2024 तक तमिल नायडू (TN), लक्षद्वीप और केरल का दौरा किया।

PM मोदी की तमिलनाडु यात्रा की मुख्य बातें:

2 जनवरी 2024 को तमिलनाडु की अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली (त्रिची) जिले में **20,000 करोड़ रुपये** से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

- ये परियोजनाएँ TN में रेल, सड़क, तेल और गैस और शिपिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थीं।
- ये विकास परियोजनाएं यात्रा को बढ़ावा देंगी और TN में रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेंगी।

रेलवे क्षेत्र से संबंधित विकास परियोजनाएँ:

PM मोदी ने राष्ट्र को रेल क्षेत्र की परियोजनाएं समर्पित कीं, जिनमें शामिल हैं,

i.41.4 km लंबे सेलम-मैग्नेसाइट जंक्शन-ओमालूर-मेट्टूर बाँध खंड का दोहरीकरण;

ii.मदुरै-तूतीकोरिन तक 160 km के रेल लाइन खंड का दोहरीकरण;

iii.रेल लाइन विद्युतीकरण के लिए तीन परियोजनाएं अर्थात तिरुचिरापल्ली-मनमदुरै-विरुधुनगर; विरुधुनगर - तेनकासी जंक्शन; सेनगोट्टई - तेनकासी जंक्शन - तिरुनेलवेली - तिरुचेंदूर।

सड़क क्षेत्र से संबंधित विकास परियोजनाएँ:

i.PM मोदी ने राष्ट्र को पांच सड़क क्षेत्र परियोजनाएं समर्पित कीं, जिनमें शामिल हैं,

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-81 के त्रिची-कल्लागम खंड के लिए 39 km लंबी चार-लेन सड़क।
- NH-81 के कल्लागम-मीनसुरूट्टी खंड की 60 km लंबी 4/2-लेनिंग।
- NH-785 के चेट्टीकुलम-नाथम खंड की 29 km लंबी चार-लेन सड़क।
- NH-536 के कराइकुडी-रामनाथपुरम खंड के पक्के कंधे के साथ 80 km लंबी दो लेन।
- NH-179A सेलम - तिरुपथुर - वानियमबाड़ी सड़क के 44 km लंबे खंड का चार लेन।

ii.PM मोदी ने सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें NH-332A के मुगैयुर से मरक्कनम तक 4-लेन सड़क के 31 km लंबे हिस्से का निर्माण शामिल है।

तमिलनाडु के लिए अन्य प्रमुख परियोजनाएँ:

i.PM ने कोरोमंडल तट, चेन्नई, TN पर कामराजर बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ-II (ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट टर्मिनल-II एंड कैपिटल ड्रेजिंग फेज -V) का उद्घाटन किया।

ii.उन्होंने 9000 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

iii.उन्होंने देश को 2 पाइपलाइन परियोजनाएं भी समर्पित कीं जिनमें शामिल हैं,

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की 488 km लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन IP101 (चेंगलपेट) से एन्नोर - तिरुवल्लूर - बेंगलुरु - पुडुचेरी - नागापट्टिनम - मदुरै - तूतीकोरिन पाइपलाइन के IP 105 (सयालकुडी) खंड तक है।
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की 697 km लंबी विजयवाड़ा-धर्मपुरी मल्टीप्रोडक्ट (POL) पेट्रोलियम पाइपलाइन (VDPL)।

iv.उन्होंने इनका शिलान्यास भी किया

- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) द्वारा कोच्चि-कुट्टनाड-बैंगलोर-मैंगलोर गैस पाइपलाइन II (KKBMPL II) के कृष्णागिरि से कोयंबटूर खंड तक 323 km लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विकास।
- वल्लूर, चेन्नई में प्रस्तावित जमीनी टर्मिनल के लिए कॉमन कॉरिडोर में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (POL) पाइपलाइनों की स्थापना।

v.उन्होंने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), कलपक्कम में डेमोंस्ट्रेशन फ़ास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट (DFRP) का भी उद्घाटन किया।

- यह अपनी तरह का अनोखा DFRP है जिसे 400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। यह फ़ास्ट रिएक्टरों से निकलने वाले कार्बाइड और ऑक्साइड फ्यूल दोनों को पुन: संसाधित कर सकता है।
- स्वदेश में विकसित यह प्लांट परमाणु ऊर्जा उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

vi.उन्होंने तिरुचिरपल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) के 500 बिस्तरों वाले लड़कों के छात्रावास "AMETHYST" का भी उद्घाटन किया।

त्रिची हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन:

PM मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। दो-स्तरीय नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन को 1100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया था।

विशेषताएँ:

i.इसमें सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों और पीक आवर्स के दौरान लगभग 3500 यात्रियों को सेवा देने की क्षमता है।

ii.यह विभिन्न कला रूपों जैसे: कोल्म कला से लेकर श्रीरंगम मंदिर के रंग को प्रदर्शित करता है।

iii.टर्मिनल के जमीनी स्तर पर, मुख्य प्रवेश द्वार में विशाल मंदिर मीनार जैसी संरचना है जो श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर के राजगोपुरम जैसा दिखता है।

PM भारतीदासन विश्वविद्यालय में 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए

अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरपल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख लोग: R.N. रवि, TN के राज्यपाल और भारतीदासन विश्वविद्यालय के चांसलर, M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (CM), और L मुरुगन, केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB)

PM ने श्रीरंगम पर एक कॉफी टेबल बुक भेंट की

अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी को तमिलनाडु के BJP अध्यक्ष K. अन्नामलई द्वारा **"श्रीरंगम - द रेस्पेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा"** नामक कॉफी टेबल बुक भेंट की गई।

बुक के बारे में:

i.इसे 23 दिसंबर, 2023 को श्री रंगनाथस्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादसी उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। इसे द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।

ii.बुक में 454 पृष्ठ हैं और यह 11 खंडों में विभाजित है। यह मंदिर और इसकी वास्तुकला, सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की मुख्य बातें:

प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में **1150 करोड़ रुपये** की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजना में विभिन्न क्षेत्र: प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल हैं।

KLI-SOFC की शुरुआत:

PM मोदी ने कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन (KLI-SOFC) परियोजना की शुरुआत की, जो लक्षद्वीप द्वीप पर धीमी इंटरनेट गति की चुनौती से निपटने में मदद करेगी।

i.यह इंटरनेट स्पीड को 100 गुना से अधिक यानी 1.7 Gbps से 200 Gbps तक बढ़ा देगा।

ii.यह इंटरनेट सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाएगा।

नोट: इस परियोजना की घोषणा PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले, नई दिल्ली में अपने स्वतंत्रता भाषण के दौरान की थी।

अन्य विकास परियोजनाएँ:

i.PM मोदी ने कदमत में लौ टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन (LTTD) प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया जो हर दिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करेगा।

ii.उन्होंने अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह के सभी हाउसहोल्ड में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस (FHTC) का भी उद्घाटन किया।

ये परियोजनाएं लक्षद्वीप के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेंगी और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगी।

iii.उन्होंने लक्षद्वीप की पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना, कावारत्ती में सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। इससे डीजल आधारित बिजली उत्पादन प्लांट्स पर निर्भरता कम होगी।

iv.उन्होंने कावारत्ती में इंडिया रिजर्व बटालियन (IRBn) परिसर में नए प्रशासनिक ब्लॉक और 80 पुरुष बैरक का भी उद्घाटन किया।

v.उन्होंने कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के उन्नयन की आधारशिला रखी।

vi.5 द्वीपों में आंगनवाड़ी केंद्रों (नंद घरों) के पांच मॉडलों का निर्माण: एंड्रोथ, चेटलाट, कदमत, अगत्ती और मनिकॉय हैं।

PM मोदी की केरल यात्रा की मुख्य बातें:

3 जनवरी 2024 को, PM मोदी ने अपनी केरल यात्रा के दौरान त्रिशूर में एक मेगा सड़कशो किया। उन्होंने केरल के त्रिशूर के थेक्किंकडु मैदान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के महिला सम्मेलन "श्रीत्री शक्ति मोदिक्कोप्पम" को भी संबोधित किया।

- इस कार्यक्रम में ASHA, MGNREGA(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम) और आंगनवाड़ी से जुड़ी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
- इस आयोजन का उद्देश्य महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में केंद्र सरकार द्वारा हासिल किए गए प्रमुख मील के पत्थर को उजागर करना है।
- इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की कुछ प्रतिष्ठित महिलाओं: शोभना (अभिनेता), मिन्नुमणि (क्रिकेटर), बीना कन्नन (उद्यमी) वैकोम विजयलक्ष्मी और मारियाकुट्टी (गायिका) ने भाग लिया।

तमिलनाडु के बारे में:

मुख्यमंत्री– M.K. स्टालिन

राज्यपाल– R.N. रवि

हवाई अड्डा– कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

राष्ट्रीय उद्यान- मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, आनमलई टाइगर रिजर्व

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में:

राजधानी– कावारत्ती

उपराज्यपाल– प्रफुल्ल खोड़ा पटेल

राष्ट्रीय उद्यान- मिनिकॉय द्वीप, अगत्ती द्वीप

हवाई अड्डा– अगत्ती हवाई अड्डा

30 दिसंबर 2023 को PM मोदी की अयोध्या (उत्तर प्रदेश) यात्रा का अवलोकन

30 दिसंबर 2023 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के उद्घाटन और शुभारंभ के लिए अयोध्या, उत्तर प्रदेश का दौरा किया:

- PM ने अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
- पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, दो अमृत भारत और छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
- महर्षि वाल्मिकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया।
- मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई राम मूर्ति को अयोध्या के राम मंदिर के लिए चुना गया।

PM ने अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में 15,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी

प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया और अयोध्या धाम में 15,700 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमे शामिल है

i.अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए **11,100 करोड़ रुपये** जिसमें शामिल हैं

- 2180 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप का विकास और लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना।
- अयोध्या में 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण और नया घाट से लक्ष्मण घाट तक पर्यटक सुविधाएं।
- गुप्तार घाट और राजघाट के बीच नए कंक्रीट घाट और पूर्व निर्मित घाटों का पुनर्वास।
- राम की पैड़ी पर दीपोत्सव और अन्य मेलों हेतु दर्शक दीर्घा का निर्माण।
- राम की पैड़ी से राजघाट और राजघाट से राम मंदिर तक तीर्थ पथ का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण।
- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)-28 (नया NH-27) लखनऊ-अयोध्या खंड का शिलान्यास और मौजूदा अयोध्या बाईपास NH-28 (नया NH-27) का सुदृढ़ीकरण और संशोधन।
- अयोध्या में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग & टेक्नोलॉजी (CIPET) केंद्र की स्थापना तथा नगर निगम अयोध्या और अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय का निर्माण कार्य।

ii.उत्तर प्रदेश भर में अन्य परियोजनाओं से संबंधित **4600 करोड़ रुपये** की परियोजना जिसमें शामिल है

- गोसाईं की बाजार बाईपास-वाराणसी (घाघरा ब्रिज-वाराणसी) (NH-233) का चार लेन चौड़ीकरण
- NH-730 के खुटार से लखीमपुर खंड का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन
- अमेठी जिले के त्रिशुंडी में LPG प्लांट की क्षमता वृद्धि
- पंखा में 30 MLD और जाजमऊ, कानपुर में 130 MLD का मलजल उपचार संयंत्र
- उन्नाव जिले में नालों का अवरोधन और मार्ग परिवर्तन और मलजल उपचार कार्य
- कानपुर के जाजमऊ में टेनरी क्लस्टर के लिए सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (CETP)।

PM ने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, दो अमृत भारत और छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई

i.पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे (**अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन** के रूप में जाना जाता है) का चरण। **240 करोड़ रुपये** से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

- आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ तीन मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन बिल्डिंग|
- यह स्टेशन '**इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) सर्टिफाइड ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग**' है।

ii.PM ने देश में सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की दो नई श्रेणियों - लिंक हॉफमैन बुश (**LHB**) पुश-पुल टेक्नोलॉजी और बेहतर त्वरण के लिए दोनों छोर पर लोको के साथ अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ट्रेनें यहां से चलती हैं:

- दरभंगा-अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल
- मालदा टाउन-सर M. विश्वेश्वरैया टर्मिनस (बेंगलुरु, कर्नाटक)

iii.प्रधानमंत्री ने छह नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसमे शामिल है

- श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली
- अमृतसर-दिल्ली
- कोयंबटूर-बैंगलोर कैंट
- मैंगलोर-मडगांव
- जालना-मुंबई
- अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल

iv.उन्होंने 2300 करोड़ रुपये की तीन रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसमे शामिल है

- रूमा चकेरी-चंदेरी तीसरी लाइन परियोजना
- जौनपुर-अयोध्या-बाराबंकी दोहरीकरण परियोजना के जौनपुर-तुलसी नगर, अकबरपुर-अयोध्या, सोहावल-पटरंगा और सफदरगंज-रसौली खंड
- मल्हौर-डालीगंज रेल खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना।

PM ने महर्षि वाल्मिकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया जिसका नाम महर्षि वाल्मिकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। **1450 करोड़ रुपये** से अधिक की लागत से अत्याधुनिक एयरपोर्ट का चरण 1। एयरपोर्ट की विशेषताएं हैं:

- एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग 6500 Sqm क्षेत्रफल में होगी
- यह सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा दे सकता है
- टर्मिनल बिल्डिंग का अगला भाग आगामी श्री राम मंदिर की मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है।
- अयोध्या एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग भी GRIHA - 5-स्टार रेटिंग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थिरता सुविधाओं से सुसज्जित है।

नोट: GRIHA (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट), भारत की नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के साथ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के सहयोग का उत्पाद है। देश की अपनी ग्रीन बिल्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम होने के नाते, GRIHA किसी ग्रेडिंग की संसाधन खपत, अपशिष्ट उत्पादन और समग्र पर्यावरणीय प्रभाव का विश्लेषण करता है।

मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई राम की मूर्ति को अयोध्या के राम मंदिर के लिए चुना गया

'प्राण प्रतिष्ठा (कोंसीक्रेशन)' के लिए भगवान राम लला की 51 इंच लंबी मूर्ति को अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकला कलाकार अरुण योगीराज ने बनाया था। PM 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे|

अरुण योगीराज के कुछ कार्य:

- सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, जो इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति के पीछे प्रदर्शित है
- केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति

- मैसूरु में B R अंबेडकर की मूर्ति
- मैसूर महाराजा जयचामाराजेंद्र वोडेयार की संगमरमर की पत्थर की मूर्ति
- मैसूरु के चुंचनकट्टे में हनुमान मूर्ति
- मैसूरु में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद संगमरमर की पत्थर की मूर्ति
- कर्नाटक में नंदी की अखंड मूर्ति
- भारत के विभिन्न मंदिरों में बाणशंकरी देवी की मूर्ति

नोट -

यह मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक **नागर शैली** में बनाया गया है।

अतिरिक्त-

PM अयोध्या में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10वीं करोड़ लाभार्थी मेरा मांझी के घर गए।

<u>उत्तर प्रदेश (UP) के बारे में:</u>

मुख्यमंत्री– योगी आदित्यनाथ

राज्यपाल– आनंदीबेन पटेल

पक्षी अभ्यारण्य- पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य; लाख-बहोसी पक्षी अभ्यारण्य

त्यौहार–जन्माष्टमी; ताज महोत्सव

PM नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा का अवलोकन

प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी 12 जनवरी, 2024 को महाराष्ट्र की आधिकारिक यात्रा पर थे।

i.अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी ने नवी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया।

ii.उन्होंने 12,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

PM मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया:

PM ने नवी मुंबई, महाराष्ट्र में "**अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी-न्हावा शेवा अटल सेतु**" नामक मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) का उद्घाटन किया।

यह 21.8 km लंबा 6-लेन पुल भारत का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल बन गया है।

अटल सेतु के बारे में:

i.पुल का लगभग 16.5 km हिस्सा समुद्र के ऊपर है और 5.5 km जमीन पर है।

ii.पुल को कुल 17,840 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।

iii.पुल की शिलान्यास PM मोदी ने दिसंबर 2016 में कि।

लाभ: इससे मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय 15-20 मिनट तक कम हो जाएगा। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।

अन्य विकास परियोजनाएँ:

i.उन्होंने **1975 करोड़ रुपये** से अधिक की लागत से विकसित **सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना के चरण 1** का उद्घाटन किया। इससे महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी और लगभग 14 लाख लोगों को लाभ होगा।

ii.PM मोदी ने भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखी जो ईस्टर्न फ्रीवेज़ के ऑरेंज गेट को मुंबई, महाराष्ट्र में मरीन ड्राइव से जोड़ेगी। यह 8700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी 9.2 km लंबी सुरंग है।

- इससे मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा और ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा।

रेल परियोजनाएँ:

PM मोदी ने करीब 2000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं।

खारकोपर-उरण लाइन का चरण 2:

PM मोदी ने खारकोपर-उरण लाइन के 14.3 km लंबे चरण 2 का उद्घाटन किया, जो वर्तमान 12.4 km लंबे बेलापुर/नेरुल-खारकोपर खंड का विस्तार है। उन्होंने उरण रेलवे स्टेशन से खारकोपर तक EMU (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स) ट्रेन के उद्घाटन को भी हरी झंडी दिखाई।

परियोजना के बारे में:

i.इसे **2,973.35 करोड़ रुपये** की अनुमानित लागत पर बनाया गया है। परियोजना लागत **CIDCO** (महाराष्ट्र शहर और औद्योगिक विकास निगम) और भारतीय रेलवे के बीच **क्रमशः 67:33** के अनुपात में साझा की जाती है।

ii.वर्तमान में, इस मार्ग पर 40 उपनगरीय सर्विसेज संचालित हो रही हैं। उरण तक विस्तार से उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा जिसमें SEZ भी शामिल है।

अन्य रेल क्षेत्र परियोजनाएं:

i.उन्होंने खार और गोरेगांव के बीच 8.8 km लंबी छठी रेल लाइन का भी उद्घाटन किया। इसे 425 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है। यह परियोजना नवंबर 2023 में पूरी हुई।

ii.उन्होंने ठाणे-वाशी/पनवेल ट्रांस हार्बर लाइन पर एक नए उपनगरीय स्टेशन **"दीघा गांव"** का भी उद्घाटन किया। इससे मार्ग पर ठाणे और ऐरोली स्टेशनों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

PM मोदी ने भारत रत्नम का उद्घाटन किया:

PM मोदी ने भारत रत्नम का उद्घाटन किया, जो मुंबई में सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन- स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEEPZ- SEZ) में जेम एंड ज्वेलरी क्षेत्र के लिए एक **मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर (CFC)** है। यह भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर है जिसमें 3D मेटल प्रिंटिंग सहित दुनिया की सर्वोत्तम उपलब्ध मशीनें हैं।

भारत रत्नम के बारे में:

i.यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, GJEPC (जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल) भारत और SEEPZ-SEZ प्राधिकरण द्वारा प्रचारित एक सामाजिक-आर्थिक परियोजना है।

ii.इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो जेम एंड ज्वेलरी विनिर्माण उद्योग के कौशल को और बढ़ावा देगा।

यह विशेष रूप से विकलांग छात्रों सहित कारीगरों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करेगा।

iii.इसका लक्ष्य SEZ एक्सपोर्ट लक्ष्य को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 15 बिलियन करना है।

न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर (NEST)-01

PM ने मुंबई में SEEPZ-SEZ में न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टॉवर (NEST)-01 का भी उद्घाटन किया। इसे मुख्य रूप से जेम एंड ज्वेलरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे मौजूदा स्टैंडर्ड फैक्ट्री-I से स्थानांतरित किया जाएगा।

PM ने नारी शक्ति दूत ऐप लॉन्च किया

PM मोदी ने नारी शक्ति दूत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह ऐप महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति ठाकरे के दिमाग की उपज है।

ऐप राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं में उनके अधिकारों और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है जिनका वे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठा सकती हैं।

PM ने नमो महिला सशक्तिकरण अभियान लॉन्च किया

अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी ने कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के लिए जोखिम प्रदान करके महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए **नमो महिला सशक्तिकरण अभियान** शुरू किया। अभियान के तहत राज्य और केंद्र सरकार की महिला विकास योजनाओं को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा।

PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया

अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान, PM मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 (12 जनवरी 2024) के एक भाग के रूप में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया।

12 से 16 जनवरी 2024 तक आयोजित 2024 युवा महोत्सव का विषय "विकसित भारत @2047- युवा के लिए, युवा के द्वार" है।

प्रमुख लोग: केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मामले और खेल मंत्रालय (MoYAS); एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (CM); और महाराष्ट्र के उप CM देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

महाराष्ट्र के बारे में:

मुख्यमंत्री (CM)– एकनाथ शिंदे

गवर्नर– रमेश बायस

राष्ट्रीय उद्यान– नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान; चंदौली राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभ्यारण्य- भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य; भामरागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य

जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल (GJEPC) के बारे में:

GJEPC जेम एंड ज्वेलरी क्षेत्र में भारत के एक्सपोर्ट-लेड विकास को चलाने वाली शीर्ष संस्था है।

अध्यक्ष– विपुल शाह

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापित– 1966

FOREIGN VISITS

25 से 29 दिसंबर 2023 तक EAM जयशंकर की रूस यात्रा का अवलोकन

विदेश मंत्री (**EAM**) S जयशंकर भारत और रूस के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के एक भाग के रूप में 25-29 दिसंबर 2023 तक **रूस** की **5 दिवसीय यात्रा** पर थे।

बैठकें:

i.अपनी यात्रा के दौरान, EAM जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की।

ii.उन्होंने रूस के उप प्रधान मंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री **डेनिस मंटुरोव** से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा की और रूस के विदेश मंत्री **सर्गेई लावरोव** से मुलाकात की और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

EAM ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए

EAM की रूस यात्रा के दौरान, उन्होंने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र** की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु:

i.रूस 2002 में शुरू हुए कुडनकुलान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

ii.2016 से, संयंत्र की पहली बिजली इकाई 1000 MW की अपनी डिजाइन क्षमता पर काम कर रही है।

iii.परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2027 में पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा।

नोट: कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना पर एक अंतर-सरकारी समझौते पर 20 नवंबर 1988 को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी और सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत और रूस ने अगले चार वर्षों के लिए परामर्श पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

अपनी यात्रा के दौरान, EAM जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, कनेक्टिविटी, सैन्य-तकनीकी सहयोग और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान में प्रगति के लिए अगले 4 वर्षों (2024-28) के लिए परामर्श पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

- प्रोटोकॉल संबंध निर्माण को बढ़ावा देते हैं और भविष्य के परामर्श के लिए सरकारों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं।

अन्य मुख्य बातें:

i.यात्रा के दौरान, EAM ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर स्कूल नंबर 653 का दौरा किया और शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। स्कूल अपने नियमित पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हिंदी पढ़ाता है।
ii.उन्होंने डेनिस मंटुरोव के साथ रूसी उद्योग और व्यापार प्रदर्शनी का भी दौरा किया।
iii.उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए

रूस के बारे में:

राष्ट्रपति– व्लादिमीर पुतिन
राजधानी – मास्को
मुद्रा- रूसी रूबल

4 & 5 जनवरी 2024 को EAM S जयशंकर की नेपाल यात्रा का अवलोकन

केंद्रीय विदेश मंत्री (EAM) डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने **4 & 5 जनवरी 2024** को नेपाल का दौरा किया। उन्हें नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने काठमांडू में 7वीं भारत-नेपाल आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया था।

- अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों: माधव नेपाल, K.P. शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की।

मुख्य विचार:

i.नेपाल ने 10 वर्षों में 10000 MW बिजली निर्यात करने के लिए भारत के साथ दीर्घकालिक विद्युत समझौता किया।
ii.भारत और नेपाल ने चार प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) को लागू करने से संबंधित हैं।
iii.भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए नेपाल को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देगा।

भारत अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10K MW विद्युत खरीदेगा

S जयशंकर की आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत और नेपाल ने बिजली व्यापार पर दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- समझौते पर शक्ति बहादुर बस्नेत (ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
- नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के सचिव गोपाल सिद्देल और भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने अपने-अपने देशों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु:

i.समझौते के अनुसार, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 MW (मेगावाट) बिजली निर्यात करेगा।
ii.यह नेपाल में निजी संस्थाओं को बिजली के आयात और निर्यात में भाग लेने की भी अनुमति देता है।
iii.समझौते के अनुसार, भारत में विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाएँ अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से नेपाल के साथ विद्युत व्यापार में संलग्न होंगी।

भारत और नेपाल ने 7वीं भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की

भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने काठमांडू, नेपाल में आयोजित 7वीं भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1987 में हुई थी।

- बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करना था।
- बैठक के दौरान संबोधित प्रमुख क्षेत्र:

i.भूमि, रेल और हवाई संपर्क परियोजनाओं पर व्यापक चर्चा।
ii.रक्षा और सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, विद्युत, जल संसाधन और लोगों से लोगों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग।

मुख्य विचार:

i.भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई, NTPC लिमिटेड (पूर्व में -राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहयोग को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
ii.न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) पर मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण की सुविधा के लिए नेपाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी (NAST) के साथ सहयोग किया।
iii.इसके अलावा, भारत सरकार और नेपाल ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारत सरकार HICDP के कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्रदान करेगी।

- नए समझौते ने HICDP के कार्यान्वयन के लिए बजटीय सीमा को 5 करोड़ नेपाली रुपये (NPR) से बढ़ाकर **NPR 20 करोड़** कर दिया है

iv.S जयशंकर और नारायण प्रकाश सऊद ने संयुक्त रूप से तीन 132-KV क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन्स का उद्घाटन किया जिसमें शामिल हैं:

- रक्सौल-परवानीपुर लाइन का दूसरा सर्किट
- कटैया-कुशहा लाइन का दूसरा सर्किट
- नई नौतनवा-मैनहिया लाइन

भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए नेपाल को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा

EAM S जयशंकर ने घोषणा की कि भारत 2023 के भूकंप से प्रभावित नेपाल के पश्चिमी जिलों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

- यह घोषणा नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य पुनर्निर्माण परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान की गई थी।

भारत-नेपाल संबंधों का महत्व:

i.नेपाल पांच भारतीय राज्यों: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 km से अधिक की सीमा साझा करता है।
ii.नेपाल एक भूमि से घिरा देश होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर निर्भर है।

नेपाल के बारे में:

प्रधान मंत्री - पुष्प कमल दहल 'प्रचंड'
राजधानी – काठमांडू
मुद्रा – नेपाली रुपया (NPR)

भारत के विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर की ईरान यात्रा की मुख्य बातें

14-15 जनवरी, 2024 को केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम (S.) जयशंकर, विदेश मंत्रालय (MEA) तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री **डॉ. होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन** के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ईरान की आधिकारिक यात्रा पर थे।

- यह यात्रा भारत और ईरान के बीच चल रहे उच्च स्तरीय आदान-प्रदान का हिस्सा थी।
- बैठक का महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक सहयोग, कनेक्टिविटी पहल और लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंध थे।

मुख्य विचार:

i.BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की सदस्यता को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री S जयशंकर की यह पहली ईरान यात्रा थी।

- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सितंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें BRICS शिखर सम्मेलन में BRICS में शामिल हुए।
- पढ़ें 2024 में पांच नए देश BRICS में शामिल होंगे

ii.7 अक्टूबर, 2023 को गाजा संकट (इज़राइल और फिलिस्तीन युद्ध) की शुरुआत के बाद से यह भारत की ओर से ईरान की पहली मंत्री-स्तरीय यात्रा भी है।

iii.गौरतलब है कि ईरान ने हाल ही में भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है जिनके नागरिकों को ईरान की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।

यह यात्रा क्या दर्शाती है?

i.यह यात्रा भारत के जारी हमास-इजराइल संघर्ष के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधित चिंताओं को प्रदर्शित करती है जो ISIS (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया), एक आतंकी संगठन ने इरान में आतंकवादी हमले की दावा किया है, और लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में वाणिज्यिक शिपिंग पर हौथी समुद्री खतरों को लेकर चल रहे हैं।

ii.इसने **चाबहार पोर्ट** और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे** (INSTC) पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईरान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला।

भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के विकास पर समझौते पर हस्ताक्षर किये

केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री **मेहरदाद बजरपाश** से मुलाकात की और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। वहां दोनों देश भारत की पहली विदेशी पोर्ट परियोजना, चाबहार पोर्ट पर अंतिम समझौते पर पहुंच गए हैं।

- यह समझौता मूल अनुबंध का स्थान लेगा, जो केवल चाबहार में **शाहिद बेहेश्टी पोर्ट** पर भारत के संचालन को कवर करता है और हर साल नवीनीकृत किया जाता है।
- यह **10 साल** के लिए वैध होगा और स्वचालित रूप से बढ़ाया जाएगा।

नोट:

दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट में दो अलग-अलग पोर्ट, शाहिद कलंतरी और शाहिद बहश्ती शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.उन्होंने **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे** (INSTC) पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 km लंबी बहु आयामी परिवहन परियोजना है।

- इसका लक्ष्य परिवहन लागत में लगभग 30% की कटौती करना और पारगमन समय को 40 दिनों से घटाकर लगभग 20 दिन करना है।

- चाबहार पोर्ट INSTC परियोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

ii.ईरान पक्ष ने दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त परिवहन समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।

पृष्ठभूमि:

ईरान और भारत के बीच द्विपक्षीय अनुबंध पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें चाबहार विकास चरण- I के शाहिद बेहेश्टी पोर्ट को सुसज्जित करने, मशीनीकरण करने और संचालन शुरू करने के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल मूल्य था। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील पढ़ें। इस संबंध में, एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) अर्थात् **इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड** (IPGL) मुंबई, महाराष्ट्र को पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के दायरे में शामिल किया गया था।

भारत NEP में पर्शियन (फ़ारसी) को शामिल करेगा; भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बन गयी

भारत ने भारत की नई शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत **पर्शियन (फ़ारसी)** को शामिल करने के अपने निर्णय की भी घोषणा की। इसके साथ ही यह भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बन जाएगी।

- यह निर्णय ईरान और भारत के बीच सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों को उजागर करता है और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करेगा।
- यह घोषणा भारत के MEA मंत्री की उनके ईरानी समकक्ष डॉ. होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई।

प्रमुख बिंदु:

i.तमिल भारत की पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था।

ii.तमिल के बाद, संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), और उड़िया (2014) को भी भारत में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है।

iii.NEP 2020 के अनुसार **पाली, प्राकृत** और **फ़ारसी** (पर्शियन) को संरक्षित किया जाना चाहिए।

iv.संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने के लिए भाषा का 1500-2000 वर्षों का रिकॉर्डेड इतिहास होना चाहिए, और अद्वितीय होना चाहिए और किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार नहीं लिया जाना चाहिए।

v.भारतीय संविधान की **आठवीं अनुसूची** भारत की आधिकारिक भाषाओं की रूपरेखा बताती है। यह संविधान के **अनुच्छेद 344(1)** और **351** द्वारा शासित है।

MEA मंत्री S जयशंकर ने राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी से मुलाकात की

केंद्रीय मंत्री S जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के साथ भी बैठक की, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर चर्चा हुई:

- चाबहार पोर्ट विकास योजनाओं सहित ईरान-भारत समझौतों के कार्यान्वयन में तेजी लाना
- अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के लिए सहयोग
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करना, विशेषकर राष्ट्रीय मुद्राओं के माध्यम से
- अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की सुरक्षा बनाए रखना।

हाल के संबंधित समाचार:

i.ईरानी महिला अधिकार प्रचारक और 2023 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नर्गेस मोहम्मदी को सामाजिक न्याय 2023 के लिए हार्मनी फाउंडेशन के मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

ii.यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला ने जिना महसा अमिनी और ईरानी महिला विरोध आंदोलन को यूरोपीय संघ (EU) के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार, विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार 2023 (सखारोव पुरस्कार) के विजेताओं के रूप में नामित किया।

ईरान के बारे में:

राष्ट्रपति– इब्राहिम रायसी

राजधानी– तेहरान
मुद्रा– ईरानी रियाल

BANKING & FINANCE NEWS

BANKING NEWS

RBI IN NEWS

रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ़ बैंकिंग इन इंडिया 2023: RBI

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **"रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ़ बैंकिंग इन इंडिया" (2022-2023)** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।

यह रिपोर्ट भारत में बैंकिंग प्रणाली की स्थिति के बारे में व्यापक डेटा प्रदान करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

लघु वित्त बैंकों (SFB) में शीर्ष अधिकारियों और औसत कर्मचारी के बीच पारिश्रमिक का अंतर सबसे अधिक है

RBI की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अधिकारियों और औसत कर्मचारियों के बीच पारिश्रमिक में अंतर लघु वित्त बैंकों (SFB) के लिए सबसे अधिक है।

i.इसमें उल्लेख किया गया है कि SFB के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पारिश्रमिक 2022 में औसत कर्मचारी वेतन का **58.1 गुना** था।

- SFB की तुलना में, निजी क्षेत्र के बैंकों (PVSB), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के MD और CEO का पारिश्रमिक 2022 में औसत कर्मचारी वेतन का **26.1 गुना और 2.4 गुना** था।

ii.रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि शीर्ष अधिकारियों और औसत कर्मचारियों के बीच पारिश्रमिक की भारी असमानता जोखिम लेने के व्यवहार को प्रेरित कर सकती है, जो बैंक के दीर्घकालिक उद्देश्यों से समझौता कर सकती है।

iii.RBI ने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है जिसके अनुसार कुल मुआवजे का न्यूनतम 50% परिवर्तनशील होना चाहिए।

- इससे पारिश्रमिक की ऐसी असमानता और प्रोत्साहन-आधारित मुआवजा संरचना के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

भारत में विभिन्न बैंकों के लिए परिवर्तनीय वेतन (VP) पर RBI डेटा:

- निजी क्षेत्र के बैंकों (PVB) के लिए, कुल पारिश्रमिक में परिवर्तनीय वेतन का हिस्सा **31% (मार्च-अंत 2021 में) से बढ़कर 39% (मार्च-अंत 2022 में)** हो गया।
- SFB के लिए, इसी अवधि के दौरान यह 25% से थोड़ा बढ़कर 26% हो गया।
- PVB के लिए परिवर्तनीय वेतन में गैर-नकद घटकों की हिस्सेदारी 78% (2021) से घटकर 57% (2022) हो गई।
- इसी तरह, SFB के लिए 41% (2021) से घटकर 34% (2022) हो गया।

RBI ने सहकारी बैंकों के साथ लघु वित्त बैंकों (SFB) के अंतर्संबंध को चिह्नित किया

RBI ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी बैंकों से उच्च दर पर जमा पर SFB की अधिक निर्भरता देखी।

i.इसने सहकारी बैंकों के साथ SFB के उच्च अंतर्संबंध को दिखाया, जिसका अर्थ है कि सहकारी बैंकों को कोई भी झटका सीधे SFB को प्रभावित करेगा।

ii.लघु वित्त बैंकों द्वारा सहकारी बैंक से बड़ी राशि उधार लेने का एक मुख्य कारण कम **चालू खाता और बचत खाता (CASA) जमा** है।

- मार्च-अंत 2023 तक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल SFB जमा लगभग **91 लाख करोड़** है और जिसमें से **67.53%** सावधि जमा है, शेष राशि CASA जमा के लिए जिम्मेदार है।
- इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि SFB का क्रेडिट-जमा अनुपात लगभग 92% रहा जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) से अधिक है।

iii.इसने NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) और MFI (सूक्ष्म वित्त संस्थान) जैसी संस्थाओं को आगाह किया, जिन्हें लघु वित्त बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास असुरक्षित सूक्ष्म ऋणों की अधिक हिस्सेदारी थी।

<u>लघु वित्त बैंकों (SFB) के बारे में:</u>

ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949) और RBI अधिनियम (1934) के तहत RBI द्वारा विनियमित और शासित होते हैं।

- वे मुख्य रूप से बैंकिंग सेवाएं और आबादी के वंचित वर्गों जैसे सूक्ष्म और लघु उद्योग, किसान और असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को ऋण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- भारत में सक्रिय SFB के उदाहरण: उज्जीवन लघु वित्त बैंक, इक्विटास लघु वित्त बैंक।

शहरी सहकारी बैंकों को निदेशकों की सेवानिवृत्ति से बचना होगा: RBI

रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने **शहरी सहकारी बैंकों (UCB)** से आग्रह किया कि उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949) के प्रावधानों के अनुसार, अपने निदेशकों के बहुत लंबे और निरंतर कार्यकाल को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- इससे अनुचित प्रभाव को कम करने के साथ-साथ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।
- इसमें उल्लेख किया गया है कि नए निदेशकों को शामिल करने से बोर्ड में नए विचार और दृष्टिकोण आएंगे।

i.इसने आगाह किया कि व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति के अभाव में, कुछ UCB बाहरी और आंतरिक जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।

ii.रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 के अंत तक, भारत में **कुल 1502 UCB** कार्यरत थे।

- लेकिन, इसने यह भी रेखांकित किया कि लगभग 33.33% (1/3) नए लाइसेंस प्राप्त UCB वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो गए हैं।
- RBI ने 2004-05 में अव्यवहार्य UCB के व्यवहार्य संस्थाओं के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू की।
- UCB क्षेत्र में 2004 से लगभग 150 UCB का विलय हुआ है, जिसमें 3 (2022-23) शामिल हैं।
- महाराष्ट्र और गुजरात ने मिलकर कुल विलय में लगभग 80% योगदान दिया।
- 2015-16 से UCB रद्द करने की कुल संख्या 46 है।

RBI: FY23 में ऋण, अग्रिम और जमा संबंधी शिकायतों में वृद्धि

RBI ने खुलासा किया कि रिजर्व बैंक ऑफ ओम्बड्समैन में ऋण और अग्रिम, जमा से संबंधित शिकायतें क्रमशः 60%, 70% तक तेजी से बढ़ीं।

प्रमुख बिंदु:

i.आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ऋण और अग्रिम से संबंधित शिकायतों की संख्या 30,734 (FY22) से बढ़कर 59,762 (FY23) हो गई है, जिसमें साल-दर-साल आधार पर 94% की वृद्धि देखी गई है।

ii.जमा खातों से संबंधित शिकायतों की संख्या 16,989 (FY22) से बढ़कर 34,481 (FY23) हो गई है।

iii.सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और निजी क्षेत्र के बैंकों (PVB) से संबंधित शिकायतें कुल प्राप्त शिकायतों का क्रमशः 43.5%, 31.4% थीं।

iv.इंटरनेट बैंकिंग के लिए शिकायतों में केवल 2% (FY23) की वृद्धि हुई, FY21 की तुलना में 3% की कमी आई।

v.FY23 में बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन संबंधी शिकायतें बढ़कर 73% हो गईं।

vi.रिपोर्ट ने हाल ही में शुरू की गई RBI-एकीकृत लोकपाल योजना (RBI-IOS) के लिए मामूली वृद्धि का संकेत दिया:

- FY23 में **CRPC (केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र)** द्वारा कुल 4,68,854 मामलों का समाधान किया गया। यह RBI-IOS के मामलों के बोझ को कम करने में मदद करता है।

- CRPC के अंतर्गत आने वाले मामलों की सूची:

i.उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना

ii.बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना

iii.प्रत्यक्ष बिक्री और वसूली एजेंट

iv.भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) का पालन न करना

व्हाइट-लेबल ATMS भारत में ATM विकास को गति देता है

RBI की रिपोर्ट से पता चला है कि FY22 में भारत में ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (ATM) की कुल संख्या में 3.5% की वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा ATM व्हाइट लेबल ATM में थे।

i.अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) द्वारा संचालित ATM में (मार्च-अंत2023):

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ATM वृद्धि में सबसे आगे हैं, भारत में कुल ATM का 63% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है।

ii.भारत में ATM की कुल संख्या में निजी क्षेत्र के बैंकों (PVB) का योगदान 35% है। PVB ने कुल 76,975 ATM का योगदान दिया, जिनमें से लगभग 67.6% PVB ATM शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

iii.विदेशी बैंक 1783 से घटकर 1231 हो गए। ATM के लिए उनका रुझान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की ओर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति निराशाजनक है और उनके कुल ATM का केवल 0.3% है।

iv.SFB 2207 से बढ़कर 2821 (ऑन-साइट और ऑफ-साइट दोनों) हो गए।

व्हाइट-लेबल ATM के बारे में:

- व्हाइट-लेबल ATM (WLA) गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित किए जाते हैं।
- उन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकरण मिलता है
- WLA ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग सेवाएं जैसे: नकद जमा, PIN परिवर्तन, खाता जानकारी और बैंकों द्वारा जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके और भी बहुत कुछ प्रदान करता है।
- भारत की बैंकिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के ATM मौजूद हैं:

नेशनल फाइनेंशियल स्विच (NFS) भारत में सभी ATM नेटवर्क का प्रबंधन करता है। इसका प्रबंधन **नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** द्वारा किया जाता है।

i.ब्राउन लेबल ATM: ये ATM सेवा प्रदाताओं को पट्टे पर दिए जाते हैं लेकिन नकद प्रबंधन और बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान की जाती है।

ii.ऑरेंज-लेबल ATM: मुख्य रूप से शेयर लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है।

iii.येलो-लेबल ATM: मुख्य रूप से ई-कॉमर्स उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

iv.पिंक-लेबल ATM: विशेष रूप से महिला ग्राहकों के लिए उपयोग किया जाता है।

v.ग्रीन-लेबल ATM: मुख्य रूप से कृषि लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है।

अतिरिक्त जानकारी:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

- **स्थापना**: 1 अप्रैल, 1935
- **मुख्यालय**: मुंबई, महाराष्ट्र
- **गवर्नर**: शक्तिकांत दास (RBI के 25वें गवर्नर)

RBI की 28वीं फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की मुख्य बातें

RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (FSR) 2023, सितंबर 2023 का अर्ध-वार्षिक प्रकाशन जारी किया है जो फाइनेंसियल स्टेबिलिटी और इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम के लचीलेपन के जोखिमों का आकलन करता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 दिसंबर, 2023 को फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (FSR) का 28वां संस्करण जारी किया।

मुख्य विशेषताएं:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के लिए NPA श्रेणी में शीर्ष 100 उधारकर्ता खातों में से कोई भी नहीं

बड़े उधारकर्ताओं के क्रेडिट में सुधार हुआ है और यह स्वागत योग्य है कि शीर्ष 100 उधारकर्ता खाते NPA (गैर-निष्पादित संपत्ति) श्रेणी में नहीं आते हैं। मार्च 2023 तक NPA श्रेणी में शीर्ष 100 उधारकर्ता खातों की हिस्सेदारी बढ़ रही थी, जिसमें 2023-24 के दौरान कमी देखी गई है।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के ऋणों में उनकी हिस्सेदारी सितंबर 2023 के अंत तक घटकर 15.9% हो गई, जो मार्च 2023 के अंत तक 17.2% थी।

ii.इसका कारण बड़े उधारकर्ता पोर्टफोलियो में संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार है जिसने SCB के GNPA (सकल गैर-निष्पादित संपत्ति) में बड़े उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी को कम करने में योगदान दिया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बड़े उधारकर्ताओं के लिए सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात, जिसे 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित एक्सपोजर के रूप में परिभाषित किया गया है, सितंबर-अंत 2023 तक घटकर 3.8% हो गया, जो मार्च-अंत 2023 में 4.5% था।
- बड़े उधारकर्ता खातों में कुल बकाया राशि में मानक परिसंपत्तियों का अनुपात पिछले 3 वर्षों में बेहतर हुआ है।
- सितंबर 2023 में, बड़े उधारकर्ताओं के पास SCB का 44.5% ऋण था, जो मार्च 2023 में 46.4% से कम है।
- SCB में बड़े उधारकर्ताओं का GNPA मार्च 2023 में 53.9% से घटकर 51.8% हो गया।
- निवेश ग्रेड अग्रिम (रेटेड BBB और ऊपर) बड़े उधारकर्ताओं के कुल बाह्य रेटेड वित्त पोषित अग्रिमों का 90.3% था।

iii.खुदरा ऋण वृद्धि बड़े उधारकर्ताओं द्वारा उधार लेने से अधिक है।

- मार्च 2020 और सितंबर 2023 के बीच SCB द्वारा बड़े उधारकर्ताओं को दी जाने वाली सकल अग्रिम राशि में और गिरावट आई है।

RBI की रिपोर्ट में 1.7 लाख करोड़ रुपये के डेट फंड AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) को दबाव में पाया गया है

SEBI के एक अध्ययन के अनुसार, सितंबर तक 17 म्यूचुअल फंडों की ओपन-एंडेड डेट योजनाओं का 1.7 लाख करोड़ रुपये AUM दबाव में था।

- हालाँकि, RBI की फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार कुल 299 योजनाओं में से केवल 24 ही तनाव में थीं।
- सर्वेक्षण सभी योजनाओं के लिए कुल 12.4 लाख करोड़ रुपये के AUM के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपये ओपन-एंडेड ऋण योजनाओं का तनावग्रस्त AUM है।
- SEBI के आदेश के अनुसार परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां हर महीने सभी ओपन-एंडेड ऋण योजनाओं (ओवरनाइट योजनाओं को छोड़कर) का तनाव परीक्षण करती हैं।
- और तनाव परीक्षण मोचन जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों के प्रभाव का मूल्यांकन करके किया जाता है जो तरलता जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत आता है।
- ओपन-एंडेड ऋण योजनाओं के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन में RaR(जोखिम पर मोचन) और CRaR(जोखिम पर सशर्त मोचन) शामिल हैं जिन्हें सीमा सीमा से ऊपर बनाए रखने की आवश्यकता है। और फिर इन अनुपातों का बैकटेस्टिंग हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा किया जाता है।

नोट: ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की कोई परिपक्वता या लॉक-इन अवधि नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि निवेशक जब तक चाहें तब तक निवेशित रह सकते हैं। निवेशक बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी समय ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट खरीद या बेच सकते हैं।

उच्च जोखिम भार के कारण बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 71 bps गिर जाएगा

RBI फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात घटकर 71 आधार अंक (BPS) हो सकता है।

- व्यक्तिगत ऋण और नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनीज (NBFC) को दिए गए ऋण के लिए जोखिम भार में वृद्धि से गिरावट आ सकती है।
- जोखिम भार को समायोजित करने के बाद, SCB का पूंजी-जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) 71 bps से घटकर 16% होने का अनुमान है और सामान्य इक्विटी टियर 1 (CET1) 58 bps से गिरकर 13.2% हो सकता है।
- सितंबर तक, SCB का CRAR और CET1 अनुपात क्रमशः 16.8 और 13.7 था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में

गवर्नर: शक्तिकांत दास
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना: 1 अप्रैल, 1935

RBI ने पीनल चार्ज इन लोन अकाउंट्स के संबंध में निर्देशों के कार्यान्वयन की समय सीमा 1 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी है

29 दिसंबर, 2023 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उचित ऋण प्रथाओं के एक भाग के रूप में, पीनल चार्ज इन लोन अकाउंट्स के संबंध में निर्देशों के कार्यान्वयन की समय सीमा तीन महीने यानी 1 जनवरी, 2024 से **1 अप्रैल, 2024** तक बढ़ा दी।

- इस संबंध में, सभी विनियमित संस्थाओं (RE) को 1 अप्रैल, 2024 से नए ऋणों के लिए नए दंड शुल्क निर्देशों को लागू करना होगा।
- मौजूदा ऋणों के मामले में, नई व्यवस्था में परिवर्तन 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद अगली समीक्षा/नवीकरण तिथि, लेकिन 30 जून, 2024 से पहले तक नहीं सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रयोज्यता:

यह विस्तार सभी वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों (SFB), स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) सहित, भुगतान बैंकों को **छोड़कर**), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, सभी नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी -NBFC (HFC-हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित), और अखिल भारतीय फाइनेंसियल इंस्टीटूशन्स पर लागू होगा।

विस्तार के पीछे कारण:

अगस्त 2023 में RBI ने बैंकों के लिए 1 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाले लोन अकाउंट्स यानी 'फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस - पीनल चार्ज इन लोन अकाउंट्स' पर पेनाल्टी लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। बैंकों और NBFC द्वारा स्पष्टीकरण और अतिरिक्त समय की आवश्यकता के कारण, कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा दी गई है।

एक्सटेंशन के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

इन दिशानिर्देशों के पीछे उद्देश्य:

इसका उद्देश्य क्रेडिट डिसिप्लिन को प्रोत्साहित करना है, न कि अनुबंधित ब्याज दर से परे राजस्व वृद्धि करना। बैंकों के बीच विविध प्रथाओं के कारण ग्राहक विवाद होते हैं, इसलिए RBI बैंकों को निर्देश देता है कि वे ब्याज दरों में अतिरिक्त घटक जोड़ने से बचें और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

दिशानिर्देशों के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

RBI ने निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाओं के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया; बड़े UCB के लिए थोक जमा सीमा को 1 करोड़ रुपये & उससे अधिक तक बढ़ाया गया

1 जनवरी, 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा खातों और जमा को निष्क्रिय खातों और लावारिस जमा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो **1 अप्रैल, 2024** से लागू होंगे।

- ये सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/RRB सहित) और सभी सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।

RBI द्वारा ये निर्देश बैंकिंग विनियमन (BR) अधिनियम, 1949 की धारा 35A के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 26A, 51 और 56 तथा इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंधों अथवा RBI को इस संबंध में निर्देश जारी करने में सक्षम बनाने वाले किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं।

निष्क्रिय खाता क्या है?

यदि दो साल से अधिक की अवधि के लिए खाते में कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं होता है, तो बचत या चालू खाते को निष्क्रिय माना जाता है।

लावारिस जमा क्या हैं?

बचत/चालू खातों में शेष राशि, जो 10 वर्षों से संचालित नहीं की जाती है, या परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमा लावारिस जमा है।

संशोधित निर्देश:

i.जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 (iii) के अनुसार, दस साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय बैंक खातों में बिना दावे वाले क्रेडिट बैलेंस को DEA फंड योजना, 2014 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करते हुए RBI के DEA फंड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

ii.जारी किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का बैंकों द्वारा विभिन्न पहलुओं के संबंध में पालन किया जाना है, जिसमें खातों और जमा को निष्क्रिय या लावारिस के रूप में वर्गीकृत करना, समय-समय पर समीक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायत निवारण और ग्राहकों, नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने की प्रक्रियाएं शामिल हैं।

- इन निर्देशों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में लावारिस जमा को कम करने और सही मालिकों या दावेदारों को उनकी वापसी की सुविधा प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों को बढ़ाना है।

iii.बैंक उन खातों के संबंध में कम से कम **एक वार्षिक समीक्षा** करेंगे, जहां एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं हुआ है।

iv.यदि पिछले वर्ष के दौरान उनके खातों में कोई गतिविधि नहीं हुई है, तो बैंकों को तिमाही आधार पर खाताधारकों को पत्र, ईमेल या SMS (लघु संदेश सेवा) के माध्यम से सूचित करना चाहिए।

- अलर्ट में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि खाता अगले वर्ष बिना किसी गतिविधि के 'निष्क्रिय' हो जाएगा, जिससे खाताधारक को पुनः सक्रियण के लिए नए KYC दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

v.किसी खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, केवल ग्राहक द्वारा शुरू किए गए लेनदेन पर, न कि बैंक द्वारा शुरू किए गए लेनदेन पर विचार किया जाएगा।

- भले ही किसी ग्राहक के पास स्थायी निर्देश (SI)/स्वत:-नवीनीकरण निर्देश हों और कोई अन्य खाता गतिविधि न हो, इसे ग्राहक-प्रेरित लेनदेन माना जाएगा।
- बैंक-प्रेरित लेनदेन में बैंक द्वारा शुरू किए गए शुल्क, फीस, ब्याज भुगतान, जुर्माना और कर शामिल हैं।

vi.सरकारी योजना के लाभार्थियों और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए शून्य शेष खातों की निष्क्रियता को संबोधित करने के लिए, बैंकों को इन खातों को कोर बैंकिंग समाधान में अलग करने की आवश्यकता है, दो साल के गैर-संचालन के बाद उन्हें 'निष्क्रिय' वर्गीकरण से छूट देनी होगी।

vii.बैंकों को निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत किसी भी खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।

- निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

vii.बैंक नियमित रूप से वेबसाइटों या शाखाओं पर लावारिस जमा विवरण (नाम, पते, लावारिस जमा संदर्भ संख्या (UDRN)) को अद्यतन और प्रदर्शित करते हैं।

- गैर-व्यक्तिगत खाते अधिकृत व्यक्तियों के नाम दिखाते हैं लेकिन खाता संख्या, प्रकार, शेष राशि और शाखा छिपाते हैं।

viii.RBI सभी शाखाओं (गैर-घरेलू शाखाओं सहित) में निष्क्रिय खातों और लावारिस जमाओं को सक्रिय करने के लिए और खाताधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के माध्यम से KYC अद्यतन की उपलब्धता को अनिवार्य करता है।

ix.ग्राहक-प्रेरित सक्रियण के बिना निष्क्रिय खातों में कोई डेबिट लेनदेन की अनुमति नहीं है।
x.बैंक सक्रियण विवरण, वेबसाइटों/शाखाओं पर फॉर्म प्रदान करते हैं और जन जागरूकता अभियान चलाते हैं।
आधिकारिक विवरण के लिए यहां क्लिक करें

DEA फंड के बारे में:

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012, धारा 26A को BR अधिनियम, 1949 में सम्मिलित किया गया है जो RBI को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत सभी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित) को सूचित किया गया है कि वे निष्क्रिय जमा खातों को निधि में स्थानांतरित कर दें, जिन पर दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा या संचालन नहीं किया गया है या कोई जमा राशि या कोई भी राशि जो 10 वर्षों से अधिक समय से बिना दावे के रह गई है।

- इसके लिए दिशानिर्देश RBI द्वारा जनवरी 2015 में जारी किए गए थे।

DEA फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

RBI ने बड़े UCB के लिए थोक जमा सीमा को 6.66 गुना बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक कर दिया है

RBI ने टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को 15 लाख रुपये और उससे अधिक से संशोधित कर 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक कर दिया है। यह 6.66 गुना वृद्धि है।

- टियर 3 और 4 शहरों में अनुसूचित UCB में स्थित नहीं होने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को 15 लाख रुपये और उससे अधिक तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

पहले, 15 लाख रुपये और उससे अधिक की जमा राशि को सभी UCB में थोक जमा माना जाता था, जिससे ग्राहकों को बैंकों के साथ ब्याज दरों पर बातचीत करने की अनुमति मिलती थी। हालाँकि, संशोधित सीमा 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक निर्धारित होने के साथ, इस सीमा से नीचे की राशि जमा करने वाले ग्राहकों को अब एक समान ब्याज दर मिलेगी।

UCB के प्रकार:

UCB चार प्रकार के होते हैं:
टियर 1: 100 करोड़ रुपये तक की जमा
टियर 2: 100 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये के बीच जमा
टियर 3: 1,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच जमा
टियर 4: 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमा

नोट्स:

i.एक ही जिले में कार्यरत टियर 1 UCB की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए। अन्य सभी UCB के लिए, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
ii.टियर 1 UCB को निरंतर आधार पर जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWA) के 9% के जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी बनाए रखना होगा।

- टियर 2 से 4 UCB को निरंतर आधार पर 12% RWA की भारित परिसंपत्तियों के जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी बनाए रखनी होगी।

UCB के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हाल के संबंधित समाचार:

i.RBI ने RBI (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) दिशानिर्देश, 2023 जारी करके उन्हें वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए बैंकों द्वारा निवेश को वर्गीकृत करने पर अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा।

ii.RBI ने वर्ष 2023-24 के लिए NBFC के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत ऊपरी परत (UL)/NBFC-UL में 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के नाम जारी किए।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

गवर्नर – शक्तिकांत दास

उप गवर्नर - स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल देबब्रत पात्रा, M. राजेश्वर राव, T. रबी शंकर

स्थापना - 1 अप्रैल 1935

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

RBI ने कमर्शियल पेपर& नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर 2024 पर मास्टर डायरेक्शन जारी किया

3 जनवरी, 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मास्टर डायरेक्शन – RBI (कमर्शियल पेपर एंड नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ़ ओरिजिनल और इनिशियल मैच्योरिटी अपटू वन ईयर) डायरेक्शंस, 2024 जारी किए जो **1 अप्रैल, 2024** से लागू होंगे।

- ये डायरेक्शन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45J, 45K, 45L और 45W के तहत प्रदत्त शक्तियों और अधिनियम की धारा 45U के साथ पठित सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

अवधि:

i.नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर (NCD) का अर्थ **90 दिनों** से **एक वर्ष** के बीच की अवधि वाला एक सुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण है।

ii.कमर्शियल पेपर (CP) का अर्थ है वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण, जिसकी मैच्योरिटी जारी होने की तारीख से न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम एक वर्ष के बीच होती है।

दिशानिर्देश:

i.CP और NCD को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) पंजीकृत डिपॉजिटरी के साथ डीमटेरियलाइज्ड रूप में जारी और रखा जाना चाहिए।

ii.CP और NCD के लिए न्यूनतम मूल्य **5 लाख रुपये** है, इसके बाद 5 लाख रुपये के गुणक होंगे।

iii.CP की अवधि सात दिन से एक वर्ष के बीच होती है, जबकि NCD की अवधि नब्बे दिन से एक वर्ष के बीच होती है।

iv.विकल्पों (कॉल/पुट) के साथ CP/NCD जारी करने की अनुमति नहीं है, और अंडरराइटिंग या सह-स्वीकृति निषिद्ध है।

v.CP और NCD के प्राथमिक निर्गम, जिसमें जारीकर्ता को फंड भुगतान और निवेशकों को जारी करना दोनों शामिल हैं, को सौदे की तारीख से **T+ 4 कार्य दिवसों** के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

vi.वह तारीख जिस पर जारीकर्ता और निवेशक (निवेशकों) द्वारा मूल्य/दर सहित व्यापार विवरण पर सहमति व्यक्त की जाती है।

vii.किसी भी प्राथमिक CP या NCD जारी करने में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) सहित व्यक्तिगत सदस्यता, जारी की गई कुल राशि का 25% से अधिक नहीं हो सकती है।

छूट/कूपन दर

i.CP अंकित मूल्य से छूट पर जारी किए जाते हैं।

ii.NCD को अंकित मूल्य पर छूट पर या निश्चित या फ्लोटिंग रेट कूपन के साथ जारी किया जा सकता है।

iii.फ्लोटिंग रेट NCD पर कूपन वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक द्वारा अनुमोदित या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA) द्वारा अनुमोदित बेंचमार्क से जुड़ा हुआ है, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, या इसे रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित नीतिगत दरों से जोड़ा जा सकता है।

रेटिंग की आवश्यकता

CP और NCD जारी करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) द्वारा दी गई न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग **'A3'** है।

क्रेडिट वृद्धि:

i.बैंक और AIFI वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर और RBI के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के तहत CP/NCD मुद्दों के लिए स्टैंड-बाय असिस्टेंस या बैक-स्टॉप फैसिलिटी जैसी क्रेडिट वृद्धि प्रदान कर सकते हैं।

ii.कॉर्पोरेट सहित गैर-बैंक संस्थाएं, समूह इकाई द्वारा जारी CP और NCD की क्रेडिट वृद्धि के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी दे सकती हैं।

अंत उपयोग

i.CP और NCD फंड मुख्य रूप से **मौजूदा परिसंपत्तियों** और **परिचालन खर्चों** के लिए हैं।

- यदि धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो प्रस्ताव दस्तावेज़ में सटीक अंतिम उपयोग का खुलासा किया जाना चाहिए।

ii.CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)/CFO (मुख्य वित्तीय अधिकारी) से विनियामक प्रावधानों और शर्तों के उचित उपयोग और पालन की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र CP/NCD जारी होने के 3 महीने के भीतर जारीकर्ता और भुगतान करने वाले एजेंट (IPA) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए या मैच्योरिटी, जो भी पहले हो।

प्रमुख बिंदु:

i.CP और NCD ETP या रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंजों सहित OTP बाजारों में व्यापार योग्य हैं।

ii.OTP ट्रेडों के लिए निपटान चक्र T+0 या T+1 है।

iii.IPA जारी होने के दिन शाम 5:30 बजे तक क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (F-TRAC प्लेटफॉर्म) के F-TRAC ट्रेड रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म पर प्राथमिक बाजार जारी करने की रिपोर्ट करता है।

iv.CP और NCD में द्वितीयक बाजार लेनदेन की सूचना F-TRAC पर 15 मिनट के भीतर दी जाती है।

v.IPA द्वारा बायबैक तिथि पर शाम 5:30 बजे तक F-TRAC प्लेटफॉर्म पर बायबैक विवरण की सूचना दी गई।

vi.IPA द्वारा डिफ़ॉल्ट या पुनर्भुगतान के दिन शाम 5:30 बजे तक F-TRAC पर डिफ़ॉल्ट और पुनर्भुगतान के मामलों की सूचना दी जाएगी।

vii.डिपॉजिटरी CP और NCD विवरण RBI को पाक्षिक या आवश्यकतानुसार रिपोर्ट करते हैं।

viii.डिबेंचर ट्रस्टी तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर NCD की बकाया राशि और डिफ़ॉल्ट विवरण की तिमाही रिपोर्ट करता है।

योग्य जारीकर्ता:

i.CP और NCD निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी किए जा सकते हैं:

- कम्पनीज; हाउसिंग फाइनेंस कम्पनीज (HFC) सहित नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनीज (NBFC); इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT); ऑल इंडिया फाइनेंसियल इंस्टीटूशन्स (AIFI)
- 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल संपत्ति वाला कोई अन्य निकाय, बशर्ते कि निकाय कॉर्पोरेट को वैधानिक रूप से भारत में ऋण लेने या ऋण उपकरण जारी करने की अनुमति हो।
- रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त कोई अन्य इकाई है।

ii.सहकारी समितियां और **100 करोड़ रुपये** के न्यूनतम निवल मूल्य के साथ सीमित देयता साझेदारी, इन डायरेक्शनके तहत CP जारी कर सकती हैं, इस शर्त के अधीन कि जारीकर्ता द्वारा बैंकों / AIFI/ NBFC से प्राप्त सभी फंड-आधारित सुविधाएं, यदि कोई हों, को जारी करते समय मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

योग्य निवेशक:

सभी निवासी CP और NCD में निवेश कर सकते हैं।

अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 नियमों के आधार पर निवेश कर सकते हैं।

हाल के संबंधित समाचार:

i.रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल डेटा प्रदान करके आसान ऋण देने की सुविधा के लिए एक डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर होगा, जो वित्तीय खिलाड़ियों को 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का उपयोग करके निर्बाध रूप से कनेक्ट करने की अनुमति देगा।

ii.RBI ने UPI पर 'संवादात्मक भुगतान' शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे उपयोगकर्ताओं को AI-संचालित वार्तालापों के माध्यम से सुरक्षित रूप से लेनदेन शुरू करने और अंतिम रूप देने की अनुमति मिलेगी। यह सुविधा स्मार्टफोन और फीचर फोन UPI प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध होगी, जिससे पूरे भारत में डिजिटल अंगीकरण के विस्तार में मदद मिलेगी। शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में, बाद में यह अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

गवर्नर– शक्तिकांत दास

उप गवर्नर-माइकल देबब्रत पात्रा, M. राजेश्वर राव, T. रबी शंकर, और स्वामीनाथन जानकीरमन

स्थापना- 1 अप्रैल 1935

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

ग्राहक शिकायतें 30 दिनों में सूचित की जानी चाहिए: RE डायरेक्शंस , 2023 के लिए RBI IO

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मास्टर डायरेक्शन – रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (इंटरनल ओम्बड्समैन फॉर रेगुलेटेड एन्टिटीज़) डायरेक्शंस, 2023 जारी किया, जिसके अनुसार रेगुलेटेड एन्टिटीज़ (RE) और उनके इंटरनल ओम्बड्समैन (IO) को शिकायत प्राप्त करने के **30 दिनों के भीतर** ग्राहकों को अंतिम निर्णय की सूचना देनी चाहिए।

- इस निर्देश का उद्देश्य IO द्वारा ग्राहकों की शिकायतों को अस्वीकार करने से पहले गहन समीक्षा की सुविधा प्रदान करके RE के भीतर उपभोक्ता शिकायत निवारण और ग्राहक सेवा मानकों को बढ़ाना है।
- IO आमतौर पर सेवा में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों से निपटते हैं।

RBI द्वारा यह डायरेक्टिव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35A, RBI एक्ट, 1934 की धारा 45M के साथ 45L, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (विनियमन) एक्ट, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स प्रणाली एक्ट, 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

मौजूदा योजनाओं का निरसन:

नए डायरेक्शंस के जारी होने के साथ, इंटरनल ओम्बड्समैन योजना 2018 में शामिल दिशानिर्देश - बैंकों द्वारा कार्यान्वयन; नॉन-बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के लिए इंटरनल ओम्बड्समैन योजना, 2019; नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनीज द्वारा IO की नियुक्ति, 2021; और RBI (क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी-इंटरनल ओम्बड्समैन) डायरेक्शंस, 2022 निरस्त कर दिए गए हैं।

मुख्य दिशानिर्देश:

i.RE को पूरी तरह से स्वचालित शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर लागू करना होगा, जो आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से खारिज की गई सभी शिकायतों को अंतिम निर्णय के लिए 20 दिनों के भीतर IO के पास भेज देगा।

ii.यदि इंटरनल ओम्बड्समैन/डिप्टी इंटरनल ओम्बड्समैन (DIO) की नियुक्तियाँ संविदात्मक हैं, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले यह **70 वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिए।

- यदि IO/DIO का कार्यकाल निर्धारित है, तो यह **3 वर्ष** से कम नहीं होना चाहिए और **5 वर्ष** से अधिक नहीं होना चाहिए, उसी RE में पुनर्नियुक्ति या विस्तार के लिए कोई पात्रता नहीं है।

iii.IO को प्रशासनिक रूप से RE के सक्षम प्राधिकारी को और कार्यात्मक रूप से विनियमित इकाई के बोर्ड को रिपोर्ट करना चाहिए।

प्रयोज्यता:

i.भारत में 10 या अधिक आउटलेट वाले बैंकों (डायरेक्शंस के अनुसार विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले) पर लागू, निगमन स्थान की परवाह किए बिना।

ii.विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली NBFC पर लागू, जिसमें 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा लेने वाली NBFC और **5,000 करोड़ रुपये** और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली जमा स्वीकार न करने वाली NBFC, सार्वजनिक ग्राहक इंटरफ़ेस शामिल हैं।

iii.31 मार्च, 2023 या उसके बाद एक करोड़ से अधिक प्रीपेड भुगतान उपकरणों वाले सभी नॉन-बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स (NBSP) पर लागू होता है।

iv.सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए अनिवार्य।

v.इन सीमाओं वाले RE को **6 महीने के भीतर** एक IO ढांचा स्थापित करना होगा।

RBI ने टाटा पे & DigiO को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया

टाटा ग्रुप की डिजिटल पेमेंट शाखा, टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड **(टाटा पे)** को पेमेंट एग्रीगेटर (**PA**) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) से मंजूरी मिल गई है।

- RBI की मंजूरी टाटा ग्रुप को टाटा पेमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से अपनी सहायक संस्थाओं के भीतर अपने सभी ई-कॉमर्स लेनदेन को संचालित करने की अनुमति देती है।
- ग्रो (वित्तीय सेवा मंच) समर्थित आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टार्टअप, **DigiO** को भी RBI से PA लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में:

टाटा पेमेंट्स टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो टाटा ग्रुप की डिजिटल बिजनेस शाखा और सहायक कंपनी है।

प्रबंध निदेशक & मुख्य कार्यकारी अधिकारी - A.S. लक्ष्मीनारायणन

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापित - 2008

RBI ने SFB के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को दोगुना बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया

8 जनवरी, 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लघु वित्त बैंकों (SFB) के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया, और **भुगतान बैंकों को SFB के रूप में अपग्रेड** करने की अनुमति दी।

- इसके पीछे का कारण SFB की वित्तीय लचीलापन में सुधार करना और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- यह ध्यान दिया गया है कि सभी परिचालन SFB की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रमुख बिंदु:

i.लघु वित्त बैंकों (SFB) में परिवर्तित होने वाले शहरी सहकारी बैंकों (UCB) को 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता है, जिसे पांच वर्षों के भीतर 200 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना है।

ii.दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र भुगतान बैंक, संचालन के पांच साल बाद SFB रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

iii.SFB को परिचालन शुरू होने पर तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा, और बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए तत्काल सामान्य अनुमति मिलेगी।

iv.SFB और भुगतान बैंक के बीच मुख्य अंतर यह है कि SFB को ऋण देने की अनुमति नहीं है।

- SFB उधार देने और जमा स्वीकार करने जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। SFB छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, असंगठित श्रमिकों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों जैसे ग्राहकों को लक्षित करते हैं।
- भुगतान बैंक सीमित बैंकिंग सेवाएं, जैसे डेबिट कार्ड जारी करना, प्रेषण और जमा खाते प्रदान करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

गवर्नर– शक्तिकांत दास

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना- 1 अप्रैल, 1935

भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों पर 2.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक **(RBI)** ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए **तीन बैंकों**, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर लगभग 2.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड - 1.20 करोड़ रुपये :

कारण: RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करना

- ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध
- RBI (नो योर कस्टमर (KYC) दिशानिर्देश, 2016
- RBI (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016'

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड - 29.55 लाख रुपये:

कारण: 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करना।

नोट- उपरोक्त दोनों बैंकों के लिए यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया गया था।

पंजाब & सिंध बैंक - 1 करोड़ रुपये:

i.कारण: 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करना

ii.यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।

RBI ने पांच को-ऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

RBI ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए पांच कोऑपरेटिव बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये सभी दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत RBI को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए गए थे।

गुजरात स्थित नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड - 7 लाख रुपये:

कारण: प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने के निर्देशों का अनुपालन न करना, RBI (KYC) दिशानिर्देश, 2016 का अनुपालन न करना और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ मानदंडों का उल्लंघन।

गुजरात स्थित मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड - 3 लाख रुपये:

कारण: 'प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करना और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन।

गुजरात स्थित हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड - 2 लाख रुपये:

कारण: RBI द्वारा 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/चिंताओं को ऋण और अग्रिम जिसमें वे रुचि रखते हैं' और 'प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के साथ जमा की नियुक्ति' पर जारी निर्देशों का अनुपालन न करना।

तेलंगाना स्थित स्तंभाद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड - 50,000 रुपये

कारण: RBI द्वारा निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम पर जारी निर्देशों का अनुपालन न करना

तमिलनाडु स्थित सुब्रमण्यनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड - 25,000 रुपये

कारण: 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम' पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करना।

RBI ने कर्नाटक के हिरियूर अर्बन को-ऑप बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक **(RBI)** ने कर्नाटक स्थित द हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) धारा 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) और 22(3)(e) के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं करता है।

ii.बैंक परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता **DICGC अधिनियम, 1961** के प्रावधानों के अनुसार, डिपोसिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम (**DICGC**) से 5 लाख रुपये तक के डिपोसिट इंश्योरेंस दावे का हकदार है।

iii.कोऑपरेटिव समितियों के रजिस्ट्रार (कर्नाटक) बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करेंगे।

RBI का इकनोमिक ऐक्टिविटी इंडेक्स Q3FY24 में 7% की वृद्धि दर्शाता है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मासिक बुलेटिन यानी 'RBI बुलेटिन - जनवरी 2024' में ' स्टेट ऑफ द इकोनॉमी' शीर्षक वाले एक लेख के अनुसार, RBI के आर्थिक गतिविधि सूचकांक (EAI) ने 2023-2024 की तीसरी तिमाही **(Q3FY24)** (अक्टूबर 2023 – दिसंबर 2023) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि को **7%** पर डाल दिया है।

- यह दिसंबर 2023 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में Q3FY24 के लिए **6.5%** के वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान से अधिक है।
- हालाँकि, यह लेख RBI के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

नोट: EAI एक नाउकास्ट (सशर्त पूर्वानुमान) है जो GDP की गतिशीलता को ट्रैक करके विकास और आउटपुट को मापने के लिए 27 संकेतकों का उपयोग करता है और विभिन्न मापदंडों पर मंदी के प्रभाव का दस्तावेजीकरण करता है।

प्रमुख बिंदु:

i.भारत की इकोनॉमी मजबूत घरेलू मांग के कारण बाहरी चुनौतियों का सामना करने में लचीली बनी रही।

ii.2023-24 वित्तीय वर्ष में उम्मीद से बेहतर वृद्धि देखी गई, जो उपभोग से निवेश की ओर बदलाव से समर्थित है।

iii.उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण दिसंबर 2023 की हेडलाइन मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़कर 5.7% हो गई।

iv.GDP का 57% हिस्सा रखने वाली निजी खपत, क्रमिक ग्रामीण आर्थिक पुनरुद्धार के बीच संघर्ष कर रही है।

v.2024-25 के लिए लक्ष्य स्थिर व्यापक आर्थिक माहौल में कम से कम 7% की वास्तविक GDP वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए गति बनाए रखना है।

ज़ोमैटो पेमेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई

नई दिल्ली स्थित ज़ोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (**ZPPL**) को 24 जनवरी 2024 से '**ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (PA**)' के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक **(RBI)** से प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

- प्राधिकरण ZPPL को अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे भोजन वितरण और रेस्तरां खोज से परे इसकी भूमिका का विस्तार होता है।

- ZPPL ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म **ज़ोमैटो लिमिटेड** (जिसे पहले ज़ोमैटो प्राइवेट लिमिटेड और ज़ोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे **2021** में शामिल किया गया था।

नोट: कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना प्रदाता **स्ट्राइप, इंक.** को भी **15 जनवरी 2024** से ऑनलाइन PA के रूप में कार्य करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है।

SEBI

SEBI ने 1 जुलाई, 2024 से ग्राहकों के ट्रेडिंग अकाउंट को स्वैच्छिक रूप से फ्रीज करने की अनुमति दी

12 जनवरी 2023 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अधिसूचित किया कि निवेशकों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए रूपरेखा 1 अप्रैल 2024 को या उससे पहले रखी जाएगी और 1 जुलाई 2024 से लागू की जाएगी।

- यह जानकारी SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रदान की गई है, जिसे SEBI (स्टॉक ब्रोकर्स) विनियम, 1992 के विनियमन 30 के साथ पढ़ा जाता है, ताकि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके और प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

रूपरेखा के बारे में:

i.इस रूपरेखा को ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (ISF) द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के तत्वावधान में और पूंजी बाजार नियामक के परामर्श से विकसित किया जाएगा।

ii.यह रूपरेखा ट्रेडिंग अकाउंट्स तक स्वैच्छिक रूप से ऑनलाइन पहुंच को रोकने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है। इसमें यह विवरण शामिल है कि ग्राहक अकाउंट अवरोधन, प्रसंस्करण समय सीमा और संचार प्रोटोकॉल का अनुरोध कैसे कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों को 1 जुलाई, 2024 से ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

कारण:

ट्रेडिंग अकाउंट्स में संदिग्ध गतिविधियों पर निवेशकों की चिंताओं के परिणामस्वरूप ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सुविधा का प्रस्ताव दिया गया, जबकि निवेशकों के लिए डीमैट अकाउंट्स को स्वैच्छिक रूप से ब्लॉक करना पहले से ही मौजूद है, प्रस्ताव अब इस विकल्प को उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स तक भी विस्तारित करता है।

- डीमैट अकाउंट निवेशकों को अपने वित्तीय उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनुमति देते हैं, जबकि, ट्रेडिंग अकाउंट, वास्तव में शेयर बाजार में व्यापार करते हैं।

आधिकारिक अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

ट्रेडिंग अकाउंट: ट्रेडिंग अकाउंट एक निवेश अकाउंट है जो खुदरा निवेशकों को प्रतिभूतियां खरीदने या बेचने में मदद करता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ खोला जाता है, जो बदले में, स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करता है, और अकाउंटधारक की ओर से ट्रेडों के निष्पादन की अनुमति देता है। यह डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:

SEBI पूंजी बाजार के लिए नियामक प्राधिकरण है। इसे 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और SEBI इंडिया अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के प्रावधान 30 जनवरी 1992 को लागू हुए।

अध्यक्ष– माधबी पुरी बुच

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

SEBI अध्यक्ष ने CDSL के लिए दो अनूठी बहुभाषी पहल शुरू कीं

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(SEBI)** की अध्यक्ष, माधबी पुरी बुच ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड **(CDSL)** के लिए **बहुभाषी CAS** और **CDSL बडी सहायता 24×7 चैटबॉट** नामक दो अद्वितीय बहुभाषी पहल शुरू की हैं। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के बीच व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

- यह पहल CDSL की **25वीं** वर्षगांठ (रजत जयंती वर्ष) कार्यक्रम में शुरू की गई थी जो मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी।

बहुभाषी CAS:

i.निवेशक 23 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी CDSL में रखी गई प्रतिभूतियों का अपना समेकित खाता विवरण (CAS) तैयार कर सकते हैं।

ii.इस पहल का नाम **आपका CAS - आपकी ज़ुबानी** है।

CDSL बडी सहायता 24×7 चैटबॉट:

i.चैटबॉट निवेशक को चार भाषाओं में चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करता है।

ii.चैटबॉट का उद्देश्य निवेशकों की 'आत्मनिर्भरता' या सेल्फ-सफिसिएन्सी की यात्रा को सरल बनाना है।

नीव अभियान:

i.25वीं वर्षगांठ समारोह में CDSL के 'नीव' अभियान का समापन हुआ।

ii.इस अभियान का लक्ष्य भारत के 25 शहरों में सशस्त्र बलों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न समुदायों के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाना है।

थॉट लीडरशिप रिपोर्ट:

i.'रीइमेजिन डिजिटल ट्रस्ट इन कैपिटल मार्केट्स'पर थॉट लीडरशिप रिपोर्ट: इस कार्यक्रम में **रिपोर्ट** का अनावरण किया गया।

ii.रिपोर्ट CDSL द्वारा नॉलेज पार्टनर्स KPMG के सहयोग से तैयार की गई थी।

iii.रिपोर्ट CDSL के डिजिटल विश्वास, वैश्विक वित्तीय अंतर्संबंध और उभरते साइबर खतरों के खिलाफ लचीलेपन के बारे में बात करती है।

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) के बारे में:

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) एशिया की पहली सूचीबद्ध डिपॉजिटरी और भारत की एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटरी है।

प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - नेहल वोरा

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापित – 1999

SEBI ने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कर्मचारियों को बिक्री की पेशकश के लिए फ्रेमवर्क जारी की

23 जनवरी, 2024 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने BSE (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और NSE(नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) जैसे स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के माध्यम से कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री की पेशकश (OFS) के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है।

- अधिसूचित प्रावधान परिपत्र जारी होने के 30वें दिन **(22 फरवरी, 2024)** से लागू होंगे।

नोट: SEBI द्वारा यह जानकारी निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 के विनियमन 51 के साथ पठित सेबी अधिनियम 1992 की धारा 11 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रदान की गई है।

OFS: OFS एक उपकरण है जहां किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक अपने शेयर सीधे जनता को बेचते हैं। इसकी शुरुआत 2012 में SEBI द्वारा की गई थी।

इस फ्रेमवर्क के पीछे कारण:

i.पात्र कंपनी के कर्मचारियों को OFS की वर्तमान प्रक्रिया स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के बाहर हो रही है जिसमें समय लगता है, अतिरिक्त लागत और कई गतिविधियां शामिल हैं।

ii.प्रतिक्रिया और हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, SEBI ने निर्णय लिया है कि प्रमोटर स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के माध्यम से OFS में कर्मचारियों को शेयर की पेशकश कर सकते हैं।

iii.यह फ्रेमवर्क दक्षता बढ़ाने, अनुपालन को आसान बनाने और लागत कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु:

i.कर्मचारियों को "कर्मचारी" नामक एक नई श्रेणी के तहत खुदरा श्रेणी के साथ **T+1 दिन** पर OFS दिया जाएगा।

- T+1 दिन का अर्थ है व्यापार से संबंधित निपटान लेनदेन के दिन से एक दिन के भीतर यानी 24 घंटे के भीतर पूरा किया गया।

ii.केवल T+1 दिन ट्रेडिंग घंटों के दौरान बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।

iii.अधिकतम बोली राशि **5 लाख रुपये** होगी। प्रत्येक कर्मचारी **2 लाख रुपये तक** के इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए पात्र है।

iv.यदि कर्मचारी भाग की सदस्यता कम है, तो शेष भाग को **2 लाख रुपये** से अधिक की बोली वाले कर्मचारियों को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जा सकता है, प्रति कर्मचारी अधिकतम **5 लाख रुपये** तक आवंटन किया जा सकता है।

v.कर्मचारियों को ऑर्डर मूल्य का 100% अग्रिम मार्जिन के रूप में नकद या नकद समकक्ष में भुगतान करना होगा।

vi.स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशनों को सलाह दिए गए परिवर्तनों को लागू करने, आवश्यकतानुसार उप-कानूनों, नियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करने और अपनी वेबसाइटों के माध्यम से बाजार सहभागियों को सूचित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

आधिकारिक अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:

अध्यक्ष– माधबी पुरी बुच

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना- 12 अप्रैल 1992

SEBI ने बाजार अफवाहों को सत्यापित करने के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए समय सीमा बढ़ा दी है

25 जनवरी 2024 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाजार अफवाह सत्यापन की समयसीमा दूसरी बार बढ़ा दी है। शीर्ष 100 कंपनियों के लिए समय सीमा 1 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 1 जून 2024 और शीर्ष 250 कंपनियों के लिए 1 अगस्त 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई।

- बाजार अफवाह सत्यापन LODR विनियमों के विनियमन 30(11) के प्रावधान के तहत है।

नोट:

SEBI द्वारा यह परिपत्र LODR (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों के विनियमन 101 के साथ पठित SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

विस्तार का विवरण:

i.प्रारंभ में यह शीर्ष 100 फर्मों के लिए 1 अक्टूबर 2023 से और शीर्ष 250 फर्मों के लिए 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी माना जाता था। इसे क्रमशः 1 फरवरी, 2024 और 1 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

ii.यह विस्तार सूचीबद्ध संस्थाओं को आसन्न परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक समय प्रदान करेगा, एक सहज परिवर्तन और नियामक ढांचे के साथ प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्रमुख बिंदु:

i.SEBI के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 और शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं को जानकारी प्रकट होने के 24 घंटों के भीतर मीडिया में रिपोर्ट की गई किसी भी विशिष्ट सामग्री घटना की तुरंत पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण देना होगा।

ii.SEBI के इन नियमों का उद्देश्य गलत बाजार भावना या किसी सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियों पर प्रभाव से बचना है।

आधिकारिक अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:

अध्यक्ष– माधबी पुरी बुच

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना- 12 अप्रैल 1992

AGREEMENTS & MoUs SIGNED

LEO और NSDL पेमेंट बैंक ने मास्टरकार्ड संचालित LEO1 कार्ड लॉन्च किया

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (NPBL) के सहयोग से एक एडु-फिनटेक स्टार्टअप **LEO1** (जिसे पहले फाइनेंसपीयर के नाम से जाना जाता था) ने **'LEO1 कार्ड'** लॉन्च किया है, जो भारत का पहला नंबरलेस प्रीपेड ID कार्ड है, जिसमें **मास्टरकार्ड** एक नेटवर्क पार्टनर के रूप में है।

- कार्ड का उद्देश्य छात्र ID कार्ड को छात्र उपयोगिता कार्ड में बदलना है।

LEO 1 कार्ड के बारे में:

i.यह कार्ड एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के साथ-साथ एक पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है।

ii.कार्ड एक वर्चुअल वॉलेट के साथ आता है जिसे LEO1 मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

iii.एक बार जब पैसा वॉलेट में जुड़ जाता है, तो इसका उपयोग किसी भी बिक्री बिंदु (**POS**) आउटलेट पर किया जा सकता है और बैंक खाता खोले बिना ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) से भी निकाला जा सकता है।

iv.कार्डधारक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

विशेषताएँ:

i.कार्डधारक प्रतिदिन अधिकतम 2 लाख रुपये तक खर्च करने की सीमा निर्धारित कर सकता है।

ii.कार्ड को मोबाइल ऐप से ब्लॉक/अनब्लॉक किया जा सकता है।

iii.यह कार्ड बेहतर धन प्रबंधन सिखाने के लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल के साथ भी आता है।

iv.कार्ड के माध्यम से खर्च करके, कार्डधारक अपने वॉलेट में इनाम और LEO सिक्के अर्जित कर सकते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने NCMC रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (**BoB**) ने **'वन नेशन, वन कार्ड'** पहल के अनुरूप नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (**NCMC**) रुपे रीलोडेबल प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है।

कार्ड के बारे में:

i.यह एक चिप-सक्षम संपर्क रहित RuPay प्लैटिनम यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा **(EMV)** प्रीपेड कार्ड है।

ii.पारंपरिक ATM कार्ड के रूप में कार्य करने के अलावा, इसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन (जैसे मेट्रो रेल, बस, ट्रेन, कैब, फेरी, टोल और पार्किंग) के पेमेंट के लिए भी किया जा सकता है।

iii.अनुमत अधिकतम ऑनलाइन वॉलेट बैलेंस 1 लाख रुपये है और अधिकतम ऑफ़लाइन वॉलेट बैलेंस 2,000 रुपये है।

iv.ऑनलाइन वॉलेट को BoB द्वारा प्रदान किए गए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से टॉप-अप किया जा सकता है जबकि ऑफ़लाइन वॉलेट को नामित NCMC टर्मिनल ऑपरेटरों पर पुनः लोड किया जा सकता है।

हाल के संबंधित समाचार:

एक्सिस बैंक लिमिटेड और सोशल वर्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (फाइब) (जिसे पहले अर्लीसैलरी के नाम से जाना जाता था) ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड, जिसे फाइब एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है।

LEO1 के बारे में:

गज्जू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली LEO1 एक गूगल इनक्यूबेटेड फिनटेक कंपनी है।

संस्थापक & प्रबंध निदेशक (MD) – रोहित गजभिए

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापित – 2017

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के बारे में:

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - देबदत्त चंद

मुख्यालय – वडोदरा, गुजरात (कॉर्पोरेट केंद्र मुंबई, महाराष्ट्र में है)

स्थापना – 1908

टैगलाइन - इंडियास इंटरनेशनल बैंक

AU SFB ने प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया

3 जनवरी 2024 को, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक **(SFB)** लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका **(USA)** स्थित मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी में कॉर्पोरेट वेतन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया '**मास्टरकार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड**' लॉन्च किया है। कार्ड को **#Swipe&Save** थीम के तहत पेश किया गया था।

कार्ड के बारे में:

i.कॉन्टैक्टलेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड कॉर्पोरेट वेतन वर्ग के लोगों को उनके दैनिक जीवन में विशेष और सुविधाजनक लाभ प्रदान करता है।

ii.कार्ड का लक्ष्य प्रत्येक खरीदारी को एक पुरस्कृत अनुभव में बदलना है।

iii.यह कार्ड एंटरटेनमेंट ऑफर, डाइनिंग ऑफर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑफर के साथ-साथ ग्रोसरीस, ट्रेवल बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग पर ऑफर प्रदान करता है।

विशेषताएँ:

i.कार्डधारक प्रति दिन 2 लाख रुपये तक की निकासी और खरीदारी कर सकते हैं।

ii.कार्ड द्वारा बनाई गई आटोमेटिक टेलर मशीन **(ATM)** फंड ट्रांसफर सीमा 20,000 रुपये तक सीमित है और कॉन्टैक्टलेस लेनदेन 5000 रुपये तक सीमित है।

बीमा कवरेज:

i.यह कार्ड 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और 25,000 रुपये तक का खरीद सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।

ii.कार्डधारक 2 लाख रुपये के कार्ड देयता कवर का भी लाभ उठा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

इस कार्ड के लॉन्च के साथ, AU SFB ने भारत में सभी पेमेंट नेटवर्क (मास्टरकार्ड, रूपे और वीज़ा) में अपने कार्ड की पेशकश का विस्तार किया है।

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - संजय अग्रवाल

मुख्यालय - जयपुर, राजस्थान
स्थापित - 1996
टैगलाइन- बदलाव हमसे है

REC & BoB ने बिजली, बुनियादी ढांचे और रसद परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

REC लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) ने तीन साल की अवधि (**2026 तक**) के लिए बिजली, बुनियादी ढांचे और रसद परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से ऋण देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (**BoB**) के साथ एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए।
MoU पर REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (**CMD**) विवेक कुमार देवांगन और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO देबदत्त चंद की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
i.MoU का उद्देश्य परिवर्तनकारी परियोजनाओं को उत्प्रेरित करना है जो समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और भारत में सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देंगे।
ii. MoU BoB की वित्तीय शक्ति के साथ बिजली क्षेत्र में REC की विशेषज्ञता को एकीकृत करता है।
नोट: REC लिमिटेड बिजली मंत्रालय **(MoP)** के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है।

IPPB और हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान में वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (**IPPB**) और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (**HZL**) ने ग्रामीण **राजस्थान** के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए हैं।
नोट: IPPB डाक विभाग, संचार मंत्रालय (MoC) के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है। HZL वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी है
हस्ताक्षरकर्ता: MoU पर IPPB के मुख्य बिक्री & विपणन अधिकारी गुरशरण राय बंसल और HZL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी **(CEO) अरुण मिश्रा** ने हस्ताक्षर किए।

MoU के बारे में:

i.MoU का उद्देश्य HZL की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी **(CSR)** गतिविधियों के लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करना है।

- इन सेवाओं में लोगों को बैंक खाते खोलने में मदद करना, पेंशन योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना, आय-सृजन ऋण देना और दीर्घकालिक बचत और निवेश विकल्प प्रदान करना शामिल है।

ii.यह MoU भारत की **असेवित और अल्पसेवित आबादी** को सर्वोत्तम श्रेणी की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की IPPB की प्रतिबद्धता से जुड़ा है।
iii.IPPB स्वयं सहायता समूह **(SHG)** की महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित 3.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाता **(BC)** बनाने के लिए सशक्त बनाता है।
iv.IPPB अपने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सरकारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का भी समर्थन करेगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (IPPB) के बारे में:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) – वेंकटराम जयंती
मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली
स्थापित – 2018
टैगलाइन- आपका बैंक, आपके द्वार

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) के बारे में:

HZL भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक है। वर्तमान में, भारत सरकार के पास HZL में 29.5% हिस्सेदारी है जबकि वेदांता के पास 64.9% हिस्सेदारी है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)- अरुण मिश्रा
मुख्यालय- उदयपुर, राजस्थान
स्थापित – 1966

SHG को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए SBI ने MORD के साथ समझौता किया

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MORD) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- MoU पर चरणजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और शांतनु पेंडसे, मुख्य महाप्रबंधक (SBI) ने हस्ताक्षर किए।

SBI ने विशेष वित्तीय उत्पाद का अनावरण किया:

SBI ने विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (**SHG**) के लिए विकसित एक विशेष वित्तीय उत्पाद **स्वयम सिद्ध** लॉन्च किया।

स्वयम सिद्ध की विशेषताएं:

i.इसका मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
ii.यह बैंक ऋण अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक व्यापक दस्तावेज़ीकरण से संबंधित चुनौतियों को कम करने और टर्नअराउंड टाइम (**TAT**) को कम करने में मदद करेगा।
iii.यह परेशानी मुक्त आवेदन प्रक्रिया प्रदान करेगा जहां KYC(अपने ग्राहक को जानें) विवरण के साथ सरल ऋण आवेदन स्थानीय SBI शाखाओं में जमा किया जा सकता है।
iv.DAY-NRLM ऋण आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ ऋण चुकौती की निगरानी करेगा।

ट्रेनिंग टूलकिट पैकेज का शुभारंभ:

SHG महिला उद्यमियों को ऋण के रूप में औपचारिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेनिंग टूलकिट पैकेज लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

i.इसे विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (**NRETP**) के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (**IFC**) के सहयोग से विकसित किया गया है।
उद्देश्य: SHG सदस्यों को उनके आर्थिक उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की क्षमताओं का विस्तार करना।

NRETP के बारे में:

NRETP को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से DAY-NRLM के तहत लॉन्च किया गया था।

- परियोजना के लिए अनुमानित कुल बजट 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और विश्व बैंक इसके कार्यान्वयन के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा।

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के बारे में:

DAY-NRLM को 2011 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है।

उद्देश्य: विभिन्न आजीविका को बढ़ावा देकर और देश भर में ग्रामीण परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके ग्रामीण गरीबी को खत्म करना।
लक्ष्य: इसने भारत के 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों और 6 लाख गांवों में **7 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों** को SHG के माध्यम से कवर करने और 8 से 10 वर्षों की अवधि के लिए उनकी आजीविका का समर्थन करने का लक्ष्य रखा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री: गिरिराज सिंह (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: बेगुसराय, बिहार)

राज्य मंत्री (MoS): साध्वी निरंजन ज्योति (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: फ़तेहपुर, उत्तर प्रदेश) और फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला, मध्य प्रदेश)

भारतीय स्टेट बैंक के बारे में:

अध्यक्ष – दिनेश कुमार खारा
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना – 1955

इंडियन बैंक ने तीन अन्य संस्थाओं के सहयोग से इंडियन बैंक वन को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

इंडियन बैंक ने FPL टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वीज़ा & नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (**NPCI**) जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी में भारतीय उपभोक्ताओं को अनुकूलित सुविधाएँ प्रदान करने के लिए '**इंडियन बैंक वन को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड**' लॉन्च किया है।

- मेटल क्रेडिट कार्ड **वीज़ा** और **रुपे** संपर्क रहित तकनीक द्वारा संचालित है।

कार्ड के बारे में:

i.को-ब्रांडेड कार्ड इंडियन बैंक द्वारा जारी किया जाएगा और FPL टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
ii.दो नेटवर्कों में परिचालन करके, कार्ड का लक्ष्य क्रेडिट पहुंच और उपयोगिता में एक नया प्रतिमान पेश करना है।
iii.यह कार्ड शून्य ज्वाइनिंग शुल्क, शून्य वार्षिक शुल्क और शून्य रिवॉर्ड रिडेम्पशन शुल्क के साथ आता है।
iv.कार्ड का उपयोग 1% विदेशी मुद्रा शुल्क के साथ दुनिया भर में किया जा सकता है।
v.यह कार्ड वास्तविक समय में लेनदेन पर नज़र रखने, खर्चों का प्रबंधन करने, खरीदारी को समान मासिक किस्त (EMI) में परिवर्तित करने, पुरस्कार छुड़ाने, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस **(UPI)** भुगतान करने, मासिक बजट की योजना बनाने, क्रेडिट सीमा को समायोजित करने और निर्बाध भुगतान की सुविधा प्रदान करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
vi.कार्डधारक **वनकार्ड मोबाइल एप्लिकेशन** के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के सभी पहलुओं को नियंत्रित कर सकता है।
नोट: वनकार्ड एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो भारतीय रिजर्व बैंक **(RBI)** द्वारा अनुमोदित बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वनकार्ड के साथ साझेदारी में जारी किया गया है। **वनरिवार्ड**, वनकार्ड का इनाम कार्यक्रम है।

इंडियन बैंक के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - शांति लाल जैन
मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
स्थापना – 1907
टैगलाइन - योर ओन बैंक

KBL और NBFC क्लिक्स कैपिटल ने MSME के लिए सह-उधार साझेदारी में प्रवेश किया

कर्नाटक बैंक लिमिटेड **(KBL)** और गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (NBFC) **क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** ने डिजिटल सह-उधार साझेदारी में प्रवेश किया है।

- साझेदारी का उद्देश्य **यूबी Co.lend प्लेटफॉर्म** के माध्यम से भारतीय सूक्ष्म, लघु & मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को ऋण प्रदान करना है।
- यह समझौता बैंकों और NBFC द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सह-उधार देने पर भारतीय रिजर्व बैंक **(RBI)** के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

इंडसइंड बैंक & ईज़ीडाइनर ने ईज़ीडाइनर इंडसइंड बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की

इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने **ईज़ीडाइनर** के सहयोग से '**ईज़ीडाइनर इंडसइंड बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड**' लॉन्च किया है, जो बिना किसी जॉइनिंग फीस के एक अद्वितीय और उन्नत डाइनिंग अनुभव प्रदान करता है, जिससे यह सभी के लिए सुलभ हो जाता है।

नोट: गुरुग्राम (हरियाणा) स्थित ईज़ीडाइनर भारत का अग्रणी खाद्य खोज, टेबल आरक्षण और रेस्टॉरेंट भुगतान प्लेटफ़ॉर्म है।

प्रमुख विशेषताऐं:

कॉम्प्लिमेंटरी ईज़ीडाइनर प्राइम मेंबरशिप:

i.यह को-ब्रांडेड कार्ड 3 महीने के लिए कॉम्प्लिमेंटरी ईज़ीडाइनर प्राइम मेंबरशिप के साथ 500 ईज़ीपॉइंट्स के जॉइनिंग बोनस के साथ आता है।

- यह कार्ड चुनिंदा रेस्टॉरेंट में डाइनिंग और टेकअवे दोनों के लिए पेईज़ी के माध्यम से ईज़ीडाइनर ऐप के माध्यम से भुगतान करने पर 500 रुपये की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है।
- यह प्रत्येक डाइनिंग अनुभव पर 50% तक की छूट प्रदान करेगा।

ii.यह 3 महीने की मेंबरशिप 2000 से अधिक प्रीमियम रेस्टॉरेंट में 25% से 50% तक की गारंटीकृत छूट प्रदान करती है।

- प्राइम मेंबरशिप के लिए कोई जॉइनिंग या एनुअल फीस नहीं है।

iii.कार्डधारक हर 90 दिनों में 30,000 रुपये खर्च करके अपनी प्राइम मेंबरशिप को नवीनीकृत कर सकते हैं।

रिवॉर्ड लाभ:

i.कार्ड प्रत्येक 100 रुपये खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने की पेशकश करता है|

ii.ईज़ीडाइनर ऐप पर खाने के बिल के बदले रिवॉर्ड पॉइंट तुरंत भुनाए जा सकते हैं।

iii.इसके अलावा, कार्डधारक हर 90 दिनों में 30,000 रुपये खर्च करने पर 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी: 2023 में, भारतीय खाद्य सेवा बाजार का आकार 69.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और 2029 तक इसके 125.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में:

MD & CEO– सुमंत कठपालिया

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापित – 1994

टैगलाइन – वी मेक यू फील रिचर

DBS बैंक इंडिया ने तमिलनाडु में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए StartupTN के साथ सहयोग किया

18 जनवरी 2024 को, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने TN में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु (TN) सरकार की एक नोडल एजेंसी StartupTN के साथ सहयोग की घोषणा की।

साझेदारी के बारे में:

i.यह साझेदारी महानगरों में StartupTN के आठ क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से TN में 1,000 से अधिक शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के साथ जुड़ेगी। यह साझेदारी **टियर 2** और **टियर 3 शहरों** में स्टार्टअप्स पर केंद्रित है।

ii.इस सहयोग का उद्देश्य मंचों पर ज्ञान साझा करके और संभावित निवेशकों के साथ स्टार्टअप्स को जोड़कर स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देना है।

iii.इसके तहत, StartupTN से जुड़े स्टार्टअप्स DBS बैंक इंडिया के 30 से अधिक एक्सेलेरेटर, इनक्यूबेटर और इकोसिस्टम इनेबलर्स के व्यापक नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार व्यापक उद्यमशील समुदाय से लाभ उठा सकते हैं।

iv.DBS बैंक इंडिया अपने साझेदार नेटवर्क के माध्यम से बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण सहायता जैसी कई मूल्य वर्धित सेवाएं भी प्रदान करेगा।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.StartupTN उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देता है।

ii.यह वर्तमान में 30 क्षेत्रों में **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग** (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI) के साथ पंजीकृत 7,400 स्टार्टअप्स का समर्थन करता है।

- इसका लक्ष्य 2026 तक 10,000 नए स्टार्टअप्स शुरू करना है

iii.DBS बैंक इंडिया वित्तीय सेवा समूह DBS सिंगापुर की सहायक कंपनी है।

- नवंबर 2020 में, लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) का DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के बारे में:

प्रबंध निदेशक & CEO– सुरोजीत शोम

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना- 1994

टैगलाइन- लिव मोर बैंक लेस

NFWPIS, IndiaAI & वाधवानी फाउंडेशन ने कृषि क्षेत्र में AI का लाभ उठाने के लिए त्रिपक्षीय MoU पर हस्ताक्षर किए

कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित परिवर्तन में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति **(NFWPIS)**, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के तहत **IndiaAI** और **वाधवानी फाउंडेशन** के बीच एक **त्रिपक्षीय** समझौता ज्ञापन **(MoU)** पर हस्ताक्षर किए गए।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.IndiaAI 30 मई 2020 को लॉन्च किया गया भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल है। यह भारत में एक एकीकृत AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और पोषित करने के लिए समर्पित है। DIC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी है।

ii.NFWPIS कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत एक सोसायटी है। यह प्रधान मंत्री (PM)-किसान योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निगरानी इकाई (PMU) है।

MoU के बारे में:

i.MoU के अनुसार, वाधवानी फाउंडेशन AI रणनीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में MoA&FW का समर्थन करेगा और इसका लक्ष्य AI के लिए MeitY की राष्ट्रीय योजना के साथ संरेखित AI-संचालित डिजिटल कृषि में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

ii.फाउंडेशन भारत को AI-संचालित डिजिटल कृषि परिवर्तन में वैश्विक नेता बनने में सहायता करेगा। यह AI के लिए MeitY की राष्ट्रीय योजना के अनुरूप है।

iii. MoA&FW ने डिजिटल कृषि को बदलने में AI के उपयोग को संस्थागत बनाने के लिए अपनी संरचना के भीतर एक समर्पित AI सेल की स्थापना की है।

प्रमुख लोग: MoA&FW के सचिव मनोज आहूजा, वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के CEO प्रकाश कुमार के साथ-साथ MoA&FW और MeitY के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली:

i.MoA&FW निजी क्षेत्र के सहयोग से **राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली** विकसित कर रहा है।

ii.AI और मशीन लर्निंग (ML) मॉडल द्वारा संचालित प्रणाली समय पर किसान हस्तक्षेप के लिए फसल के मुद्दों का पता लगाएगी और संभावित नुकसान को कम करेगी।

MoA&FW की AI तकनीकें:

MoA&FW किसानों को लाभ पहुंचाने और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य भारत में किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना भी है।

i.MoA&FW भारत डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर **(InDEA) 2.0** को बढ़ावा देता है, जो एक नेटवर्क दृष्टिकोण है, जिसे MeitY द्वारा डिज़ाइन किया गया है।

InDEA 2.0 एक ऐसा ढांचा है जो सरकारों और निजी क्षेत्र के व्यवसायों को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आर्किटेक्चर डिजाइन करने की अनुमति देता है।

ii.MoA&FW ने PM किसान सम्मान निधि योजना पर किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिए एक AI-संचालित चैटबॉट 'किसान ई-मित्र' **विकसित** किया है।

यह अन्य सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए हिंदी, तमिल, ओडिया, बांग्ला और अंग्रेजी में व्यापक समाधान प्रदान करता है।

यूनिटी बैंक ने अपने SCF प्लेटफॉर्म यूनसिया चेन के लिए यूनसिया के साथ हाथ मिलाया

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (**यूनिटी बैंक**) ने कुशल प्रसंस्करण और सटीक दैनिक ऋण लेनदेन की सुविधा के लिए अपने अत्याधुनिक सप्लाई चेन फाइनेंस (SCF) प्लेटफॉर्म **'यूनसिया चेन'** के लिए यूनसिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है।

यूनसिया चेन के बारे में:

i.यूनसिया चेन एक सुविधा संपन्न उत्पाद सूट प्रदान करता है जिसमें भौतिक आपूर्ति श्रृंखला उद्योग के सभी व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं, जो इसकी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ii.यह प्लेटफॉर्म खरीदार, विक्रेता और ऋणदाता को एक छतरी के नीचे एकजुट करता है।

iii.यह उपरोक्त तीन पक्षों के बीच होने वाली सभी ऑनबोर्डिंग और लेनदेन यात्राओं की टेम्पलेट विविधताएं प्रदान करता है।

iv.प्लेटफ़ॉर्म एक उच्च विन्यास योग्य, तीव्र परिनियोजन ढांचे के रूप में कार्य करता है।

v.यह प्लेटफॉर्म यूनिटी बैंक में 100 दिनों से भी कम समय में लॉन्च किया गया था।

यूनसिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में:

अध्यक्ष - हरि पद्मनाभन

मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु

स्थापित – 2020

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - इंद्रजीत कैमोत्रा

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापित – 2021

REC & NIIFL ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए फंडिंग सॉलूशन्सपर एक MoU पर हस्ताक्षर किए

26 जनवरी, 2024 को, **REC लिमिटेड** (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (**NIIFL**) के साथ एक समझौता ज्ञापन (**MoU**) पर हस्ताक्षर किए हैं।

नोट: REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय (MoP) के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (**CPSE**) है।
हस्ताक्षरकर्ता: दलजीत सिंह खत्री, कार्यकारी निदेशक (वित्त), REC; और **प्रसाद गडकरी**, कार्यकारी निदेशक & मुख्य रणनीति अधिकारी, NIIFL, **विवेक कुमार देवांगन**, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) की उपस्थिति में; और **राजीव धर**, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD), NIIFL।

MoU के बारे में:

i.इस MoU के तहत, REC और NIIFL भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए फंडिंग सॉलूशन्स पर मिलकर काम करेंगे।
ii. MoU फाइनेंसिंग को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए NIIF की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।

REC लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) के बारे में:

यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ नॉन-बैंकिंग फाइनेंश कंपनी (NBFC), और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (IFC) के रूप में पंजीकृत है।
CMD– विवेक कुमार देवांगन
मुख्यालय– नई दिल्ली, दिल्ली
स्थापना- 1969

OTHER BANK NEWS

WB ने सामाजिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए तीन मुद्राओं में बॉन्ड जारी किए

विश्व बैंक **(WB)** ने सदस्य देशों में हरित और सामाजिक परियोजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए तीन अलग-अलग मुद्राओं अर्थात् कैनेडियन डॉलर (CAD), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD), और संयुक्त राज्य डॉलर (USD) में बॉन्ड जारी करके धन जुटाया है।

- विश्व बैंक की शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) जारीकर्ता के रूप में कार्य करती है।

लॉन्च किए गए बॉन्ड:

i.5-वर्षीय AUD सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड - 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
ii.7-वर्षीय USD सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड - 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर
iii.5-वर्षीय CAD सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड - 1.4 बिलियन कैनेडियन डॉलर
नोट: ये बॉन्ड लक्ज़मबर्ग शहर, लक्ज़मबर्ग में लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (**LSE**) में सूचीबद्ध हैं; सभी बॉन्ड को **Aaa/AAA** रेटिंग दी गई है।

5-वर्षीय AUD सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड:

i.विश्व बैंक ने **2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर** के मूल्य के साथ 5-वर्षीय बॉन्ड लॉन्च किया है जो 10 जनवरी 2029 को परिपक्व होगा।
ii.यह पहला बेंचमार्क लेनदेन था क्योंकि इसने 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का लेनदेन आकार हासिल किया जो कि सबसे बड़ा AUD सॉवरेन, सुपरनैशनल एंड एजेंसी (**SSA**) लेनदेन है।

बॉन्ड के बारे में:

i.बॉन्ड न्यूनतम मूल्यवर्ग 1,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का है और न्यूनतम होल्डिंग 500,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर निर्धारित है।
ii.बॉन्ड की री-ऑफर मूल्य 99.878% है और री-ऑफर यील्ड 4.3275% (अर्ध-वार्षिक) है।
iii.लेन-देन के संयुक्त प्रमुख प्रबंधक डॉयचे बैंक AG, JP मॉर्गन, नोमुरा इंटरनेशनल plc और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा (RBC) कैपिटल मार्केट्स हैं।

निवेशक वितरण:

- **प्रकार के अनुसार-** बैंक/बैंक ट्रेजरी (38%), केंद्रीय बैंक/आधिकारिक संस्थान (37%), परिसंपत्ति प्रबंधक/बीमा/पेंशन फंड (25%)।
- **क्षेत्र के अनुसार-** एशिया (56%), ऑस्ट्रेलिया (22%), यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA - 22%)।

7-वर्षीय USD सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड:

WB ने निवेशकों के लिए **5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य का 7-वर्षीय बॉन्ड लॉन्च किया है और यह लेनदेन 2024 में SSA मार्केट में सबसे बड़ी ऑर्डर बुक उत्पन्न करने वाला पहला लेनदेन है।

बॉन्ड के बारे में:

i.यह उच्च गुणवत्ता वाला तरल बॉन्ड 10 जनवरी 2031 को परिपक्व होता है।

ii.बॉन्ड का मूल्य 1,000 अमेरिकी डॉलर है और कूपन दर 4.00% तय की गई है जिसका भुगतान अर्ध-वार्षिक किया जाता है।

iii.बॉन्ड का इश्यू मूल्य 99.505% और इश्यू यील्ड 4.082% (अर्ध-वार्षिक) है।

iv.लेन-देन के प्रमुख प्रबंधक बार्कलेज बैंक PLC, BMO कैपिटल मार्केट्स, BNP पारिबा और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स हैं।

निवेशक टूटना:

- **प्रकार के अनुसार** - बैंक/बैंक ट्रेजरी/कॉर्पोरेट (49%), केंद्रीय बैंक/आधिकारिक संस्थान (35%), परिसंपत्ति प्रबंधक/बीमा/पेंशन फंड (16%)
- **भूगोल के अनुसार-** यूरोप/मध्य पूर्व/अफ्रीका (EMEA -56%), USA (26%), एशिया (18%)

5-वर्षीय CAD सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड:

विश्व बैंक ने **IBRD** सदस्य देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहलों को वित्तपोषित करने के लिए **1.4 बिलियन कैनेडियन डॉलर** मूल्य का 5-वर्षीय बॉन्ड लॉन्च किया है।

- बॉन्ड 12 जनवरी 2029 को परिपक्व होने वाला है।

बॉन्ड के बारे में:

i.बॉन्ड 99.678% की मूल्य पर जारी किया जाता है और निवेशकों को 3.571% (अर्ध-वार्षिक) की उपज की पेशकश की जाती है।

ii.कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स (CIBC), रॉयल बैंक ऑफ कनाडा (RBC) कैपिटल मार्केट्स, नेशनल बैंक फाइनेंशियल और टोरंटो डोमिनियन सिक्योरिटीज संयुक्त लीड मैनेजर हैं।

iii.बॉन्ड का मूल्यवर्ग 1,000 कैनेडियन डॉलर है।

निवेशक वितरण:

- **प्रकार के अनुसार-** केंद्रीय बैंक/अधिकारी (55%), बैंक/बैंक ट्रेजरी/कॉर्पोरेट (34%), परिसंपत्ति प्रबंधक/बीमा/पेंशन फंड (11%)।
- **क्षेत्र के अनुसार-** अमेरिका (48%), एशिया (34%), यूरोप/मध्य पूर्व/अफ्रीका (18%)।

हॉल के संबंधित समाचार:

विश्व बैंक (WB) द्वारा जारी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट (IDU) अक्टूबर 2023 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY23/24) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि 6.3% पर बरकरार रखी गई है और FY24/25 के लिए वृद्धि दर 6.4% रहेगी|

विश्व बैंक के बारे में:

विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष - अजय बंगा

मुख्यालय – वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

स्थापना – 1944

ADB ने क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 साल और 10 साल की दोहरी किश्त में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड्स बेचे

एशियाई विकास बैंक (**ADB**) **एशिया और प्रशांत क्षेत्र** में अपने सदस्य देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए 3 साल की परिपक्वता के साथ **3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** और 10 साल की परिपक्वता के साथ **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य का दोहरी-किश्त वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड बेचता है।

- जुटाई गई धनराशि का योगदान ADB के सामान्य पूंजी संसाधनों में किया जाएगा।

3 बिलियन अमेरिकी डॉलर - 3 वर्ष का बॉन्ड:

i.यह 3 साल का बॉन्ड **12 जनवरी 2027** को परिपक्व होगा।

ii.बॉन्ड विवरण:

- **कूपन दर**: 4.125% प्रति वर्ष
- **कूपन भुगतान आवृत्ति**: अर्ध-वार्षिक
- **कीमत**: 99.663%
- **उपज**: 11.9 आधार अंक

iii.बॉन्ड की उपज एक बेंचमार्क के संदर्भ में है, जो दिसंबर 2026 तक 4.375% संयुक्त राज्य **(US)** ट्रेजरी नोट है।

निवेशक वितरण:

- **निवेशक प्रकार के अनुसार**- केंद्रीय बैंक और आधिकारिक संस्थान (66%), बैंक (21%), फंड मैनेजर और अन्य निवेशक (13%)
- **भूगोल के अनुसार** - यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (36%), एशिया (33%), अमेरिका (31%)

2 बिलियन अमेरिकी डॉलर - 10 वर्ष का बॉन्ड:

i.यह 10-वर्षीय बॉन्ड **12 जनवरी 2034** को परिपक्व होगा।

ii.बॉन्ड विवरण:

- **कूपन दर**: 4.125% प्रति वर्ष
- **कूपन भुगतान आवृत्ति**: अर्ध-वार्षिक
- **कीमत**: 99.530%
- **उपज**: 21.3 आधार अंक

iii.बॉन्ड की उपज एक बेंचमार्क के संदर्भ में है, जो नवंबर 2033 के कारण 4.5% US ट्रेजरी नोट है।

निवेशक वितरण:

- **निवेशक प्रकार के अनुसार**- बैंक (50%), केंद्रीय बैंक और आधिकारिक संस्थान (28%), फंड मैनेजर और अन्य निवेशक (22%)
- **भूगोल के अनुसार** - यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (54%), अमेरिका (29%), एशिया (17%)

लेनदेन:

i.BofA सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा (**RBC**) कैपिटल मार्केट्स और TD सिक्योरिटीज ने लेनदेन के प्रबंधन का बीड़ा उठाया।

ii.यह 2024 के लिए ADB का पहला अमेरिकी डॉलर वैश्विक बेंचमार्क है।

अतिरिक्त जानकारी:

i.कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स **(CIBC)** कैपिटल मार्केट्स, दाइवा कैपिटल मार्केट्स यूरोप, नेटवेस्ट मार्केट्स, स्कॉटियाबैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सहित एक सिंडिकेट समूह का भी गठन किया गया था।

ii.ADB ने 2024 में पूंजी बाजार से लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना बनाई है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बारे में:

अध्यक्ष – मासात्सुगु असकावा

मुख्यालय - मांडलुयॉन्ग शहर, मनीला, फिलीपींस

स्थापना - 1966

सदस्य - 68 देश (49 देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के भीतर और 19 बाहर से हैं)

बंधन बैंक ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'इंस्पायर' कार्यक्रम शुरू किया

बंधन बैंक लिमिटेड ने **वरिष्ठ नागरिकों** की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए '**इंस्पायर**' कार्यक्रम नामक एक नई योजना शुरू की है। यह ऐसी योजनाएं पेश करता है जो वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वृद्ध लोगों की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

पात्रता:

i.भारत में रहने वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति।

ii.प्रीमियम बचत खाते के लिए मासिक औसत शेष (MAB) 1 लाख रुपये और एडवांटेज बचत खाते के लिए 25,000 रुपये होना चाहिए।

फ़ायदे:

i.इंस्पायर कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को तरजीही ब्याज दरें, प्राथमिकता वाली बैंकिंग सेवाएं और डोरस्टेप बैंकिंग सुविधाएं जैसे लाभ प्रदान करता है।

ii.कार्यक्रम इंस्पायर सदस्यता ID कार्ड प्रदान करता है जिसमें ग्राहकों का विवरण होता है।

iii.यह कार्यक्रम जीवन देखभाल लाभ भी प्रदान करता है जैसे दवा खरीद, नैदानिक सेवाओं और चिकित्सा उपचार पर विशेष छूट।

iv.नई दिल्ली(दिल्ली) स्थित स्वास्थ्य एग्रीगेटर '**ऑक्सी**' के सहयोग से, कार्यक्रम 360 डिग्री स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं प्रदान करता है।

v.यह खुदरा सावधि जमा पर तरजीही दरें (प्रति वर्ष 6.60% तक) & बचत खाते की शेष राशि पर उच्च ब्याज दरें (प्रति वर्ष 8.05% तक) प्रदान करता है।

बंधन बैंक लिमिटेड के प्रमोटर:

बंधन बैंक लिमिटेड का प्रचार HDFC लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सितंबर 2023 तक, HDFC लिमिटेड के पास बंधन बैंक में 39.98% पेड-अप शेयर पूंजी है।

प्रमोटर:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(69) के अनुसार, प्रमोटर का अर्थ है,

i.एक व्यक्ति जिसे कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में विशेष रूप से प्रमोटर के रूप में नामित किया गया है या कंपनी द्वारा अपने वार्षिक रिटर्न में पहचाना गया है।

ii.एक व्यक्ति जो कंपनी के मामलों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है, चाहे वह निदेशक, शेयरधारक या अन्यथा हो।

iii.एक व्यक्ति जिसके निर्देशों, सलाह या निर्देशों के अनुसार किसी कंपनी के निदेशक मंडल कार्य करने के आदी हैं।

वर्ल्ड बैंक के IBRD ने 5-वर्षीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड में 1.5 बिलियन GBP जुटाया

वर्ल्ड बैंक (**WB**) की शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (**IBRD**) ने निवेशकों से **1.5 बिलियन GBP** जुटाने के लिए ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (GBP) में 5-वर्षीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड की कीमत तय की है, जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के वित्तपोषण में योगदान देता है।

नोट: IBRD ने 1959 से **ट्रिपल-A(AAA) रेटिंग** (इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग) बनाए रखी है।

बॉन्ड के बारे में:

i.बॉन्ड **2 अक्टूबर 2028** को परिपक्व होगा।

ii.यह बॉन्ड लक्ज़मबर्ग सिटी, लक्ज़मबर्ग में लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (**LSE**) में सूचीबद्ध है।

iii.लेनदेन विवरण:

- निर्गम मूल्य: 99.955%
- निर्गम उपज: 3.889% वार्षिक
- मूल्यवर्ग: GBP 1,000
- कूपन: 3.875% प्रति वर्ष
- कूपन भुगतान तिथियाँ: प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर

v.सिटीग्रुप इंक., नेटवेस्ट मार्केट्स Plc, सैंटेंडर बैंक और टोरंटो डोमिनियन सिक्योरिटीज लेनदेन के **संयुक्त प्रमुख प्रबंधक** हैं।

vi.बेल्जियम स्थित **यूरोक्लियर** और लक्ज़मबर्ग स्थित **क्लियरस्ट्रीम** लेनदेन के लिए क्लियरिंग सिस्टम सर्विस प्रदान करेगा।

vii.यह लेन-देन 2022 के बाद से सुपरनैशनल सॉवरेन एंड एजेंसी (SSA) जारीकर्ताओं के लिए सबसे बड़े GBP बेंचमार्क बॉन्ड को चिह्नित करता है।

निवेशक वितरण:

- **निवेशक प्रकार के अनुसार**- सेंट्रल बैंक्स/ऑफिसियल इंस्टीटूशन्स (53%), बैंक्स/बैंक ट्रेजरी/कॉर्पोरेट (25%), एसेट मैनेजर्स/इंस्योरेंस/पेंशन फंड (22%)।
- **भूगोल के अनुसार** - यूनाइटेड किंगडम (UK - 59%), एशिया (32%), यूरोप/मध्य पूर्व (6%), अमेरिका (3%)।

वर्ल्ड बैंक ग्रुप (WBG) की शाखाओं के बारे में:

WBG में पाँच विकास संस्थान शामिल हैं, अर्थात्,

i.इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट **(IBRD)**

ii.इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन **(IDA)**

iii.इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन **(IFC)**

iv.मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी **(MIGA)**

v.इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स **(ICSID)**

SBI ने ग्रीन प्रोजेक्ट्स के फाइनेंस के लिए ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (**SBI**) ने 5 साल के ग्रीन बॉन्ड (जिसे ग्रीन नोट्स के रूप में भी जाना जाता है) जारी करके **250 मिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटाए हैं, जो **29 दिसंबर 2028** को परिपक्व होंगे ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके जो SBI के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (**ESG**) फाइनेंस फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.जारी किए गए वरिष्ठ, असुरक्षित, ग्रीन फ्लोटिंग रेट नोट्स को स्टैंडर्ड & पूअर्स (S&P) द्वारा '**BBB-**' रेटिंग दी गई है।

ii.बॉन्ड SBI के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्यम अवधि के नोट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जारी किए गए थे।

iii.बॉन्ड सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (**SOFR**) से 1.20% ऊपर फ्लोटिंग रेट के आधार पर जारी किए गए थे।

iv.यह बॉन्ड SBI की लंदन शाखा, यूनाइटेड किंगडम (UK) द्वारा संचालित निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया गया था।

v.इसे गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में स्थित इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड **(इंडिया INX)** में सूचीबद्ध किया गया था।

vi.टोक्यो (जापान) स्थित - मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप इंक (MUFG) ने इस प्लेसमेंट के लिए एकमात्र ग्रीन नोट समन्वयक और प्लेसमेंट एजेंट के रूप में काम किया।

SBI का 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सिंडिकेटेड सोशल लोन:

i.SBI ने घरेलू ESG फाइनेंसिंग बाजार को पूरा करने के लिए सिंडिकेटेड सोशल लोन के माध्यम से सफलतापूर्वक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं।

ii.जुटाया गया 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस सिंडिकेटेड सोशल लोन का हिस्सा है।

iii.धन दो कार्यकालों के माध्यम से जुटाया गया: एक तीन साल और एक पांच साल का ऋण।

नोट:

SOFR डॉलर-डेनोमिनटेड डेरिवेटिव और लोन्स के लिए एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसने जून 2023 में लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट **(LIBOR)** को प्रतिस्थापित कर दिया।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बारे में:

अध्यक्ष – दिनेश कुमार खारा

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना – 1955

BoI ने 7.5% ब्याज पर अति विशिष्ट 175 दिनों की FD लॉन्च की

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (**PSB**) बैंक ऑफ इंडिया (**BoI**) ने 1 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाली 175 दिनों की निर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के साथ एक अति विशिष्ट सावधि जमा (FD) योजना शुरू की है।

- यह योजना 2 करोड़ रुपये से लेकर 50 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर 7.50% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु:

i.यह विशेष सावधि जमा एक सीमित अवधि की पेशकश के रूप में पेश की गई है।

ii.यह योजना विशेष रूप से घरेलू रुपया सावधि जमा के लिए है।

iii.वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष की आयु) को 6 महीने से लेकर 3 साल तक की अवधि के लिए अपनी खुदरा सावधि जमा (2 करोड़ रुपये से कम) पर 0.50% की अतिरिक्त ब्याज दर मिलेगी।

iv.अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) को समान खुदरा सावधि जमा पर अतिरिक्त 0.65% मिलेगा।

अतिरिक्त जानकारी:

वर्तमान में BoI 2 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर 175 दिन की अवधि के लिए 4.50% ब्याज दर का भुगतान करता है। 7.25% 2 साल की जमा राशि के लिए BoI द्वारा दी जाने वाली उच्चतम ब्याज दर है।

बैंक ऑफ इंडिया के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - रजनीश कर्नाटक

मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

स्थापना – 1906
टैगलाइन - रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग

HDFC बैंक ने 'UPI फॉर सेकेंडरी मार्किट' सुविधा के हिस्से के रूप में लेनदेन निष्पादित किया

HDFC बैंक लिमिटेड ने **'UPI फॉर सेकेंडरी मार्किट'** सुविधा के एक भाग के रूप में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट्स ऐप के माध्यम से लेनदेन निष्पादित किया है।

- यह "ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन सेकेंडरी मार्किट" के अनुरूप है जिसे वैकल्पिक आधार पर भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (**SEBI**) और भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुमति दी गई थी।
- यह प्राइमरी मार्किट के लिए उपलब्ध एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (**ASBA**) सुविधा के समान है।

ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन सेकेंडरी मार्किट:
आवश्यक धनराशि ब्लॉक्ड होने के साथ शेयर खरीदने वालों की धनराशि उनके बचत अमाउंट में बनी रहेगी।

इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया

इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (**NPCI**) के सहयोग से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)-सक्षम **'इंडसइंड बैंक सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड'** लॉन्च किया है।

कार्ड के बारे में:
i.संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड कार्डधारकों के दैनिक लेनदेन अनुभव को बढ़ाता है जिससे उन्हें कई सुविधाजनक पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं।
ii.कार्ड प्रत्येक स्टेटमेंट साईकल में खुदरा खर्च पर 1% कैशबैक प्रदान करता है।
iii.कार्डधारक भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए 1% रेलवे अधिभार छूट के लिए पात्र हैं।
iv.कार्डधारक ईंधन अधिभार पर 1% छूट का भी लाभ उठा सकता है।
v.कार्डधारकों को नकदी निकालने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में:
प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - सुमंत कठपालिया
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना – 1994
टैगलाइन - वी मेक यू फील रिचेर

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बारे में:
प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - दिलीप अस्बे
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापित - 2008
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 **के तहत स्थापित**

IOB ने सेविंग्स एकाउंट को ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए सेविंग्स एकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की

चेन्नई (तमिलनाडु) स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, **इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB)** ने विभिन्न स्थानों (काम या शिक्षा के लिए) जाने वाले ग्राहकों के लिए सेविंग्स एकाउंट पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए **'सेविंग्स एकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन'** योजना शुरू की।

- इस योजना का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, मैन्युअल पेपरवर्क कार्रवाई को समाप्त करना और बैंक एकाउंट को स्थानांतरित करने के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम करना है।
- एकाउंट ट्रांसफर शुरू करने के लिए, ग्राहक IOB वेबसाइट (www.iob.in) पर 'ट्रांसफर ऑफ़ सेविंग्स एकाउंट्स' अनुभाग तक पहुंच सकते हैं।

कर्नाटक बैंक & डिजिवृद्धि, डेयरी किसानों को वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए साझेदारी

कर्नाटक बैंक लिमिटेड **(KBL)** ने डेयरी किसानों और डेयरी सोसायटी की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए **डिजिवृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (DGV)** के साथ साझेदारी की है।

- ये सेवाएँ कर्नाटक दुग्ध महासंघ (**KMF**) के दुग्ध संघों से जुड़ी ग्राम डेयरी सहकारी समितियों को दी जाएंगी।

प्रमुख बिंदु:

i.DVG के साथ यह साझेदारी KBL को डेयरी किसानों के लिए सहज और अभिनव एंड-टू-एंड डिजिटल उत्पाद पेश करने में सक्षम बनाएगी।

ii.यह साझेदारी संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करेगी, डेयरी मूल्य श्रृंखला में भुगतान को आसान और डिजिटल बनाएगी।

iii.प्रारंभ में, सेवाएँ अब चामराजनगर दुग्ध संघ से जुड़ी दुग्ध समितियों को उपलब्ध कराई जाती हैं और निकट भविष्य में अन्य दुग्ध समितियाँ तक इसका विस्तार किया जाएगा।

DVG के उत्पाद:

i.DGV PAY - डेयरी किसानों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए भुगतान मूल्य श्रृंखला को सरल बनाएं

ii.DVG MONEY- अपने अद्वितीय हामीदारी तंत्र का उपयोग करके किसानों को डिजिटल कार्यशील पूंजी और गोजातीय ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

iii.DVG CONNECT- एम्बेडेड वित्तपोषण विकल्पों के साथ गोजातीय खोज, मूल्य निर्धारण और उत्पादकता में अंतराल को संबोधित करें

कर्नाटक बैंक लिमिटेड (KBL) के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - श्रीकृष्णन हरिहर सरमा

मुख्यालय - मंगलुरु, कर्नाटक

स्थापना – 1924

टैगलाइन - योर फॅमिली बैंक अक्रॉस इंडिया

डिजिवृद्धि टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (DVG) के बारे में:

DVG भारत का पहला एकीकृत डेयरी फिनटेक और मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है।

संस्थापक और MD & CEO- रागवन वेंकटेशन

मुख्यालय – बेंगलुरु, कर्नाटक

स्थापित – 2019

SBI ने मध्यम अवधि के बॉन्डों के माध्यम से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए; S&P और फिच ने BBB रेटिंग दी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को ऋण देने के लिए संसाधन जुटाने के लिए मध्यम अवधि के नोटों के माध्यम से लगभग **300 मिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटा रहा है।

- **S&P ग्लोबल रेटिंग्स** ने **SBI** की लंदन शाखा द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित डॉलर-मूल्य वाले बॉन्डों को अपनी **'BBB**-' दीर्घकालिक इश्यू रेटिंग सौंपी है।

- **फिच रेटिंग** ने इन वरिष्ठ असुरक्षित नोटों को **'BBB-(EXP)'** की अपेक्षित रेटिंग दी है।

ध्यान देने योग्य बातें:

i.नए इश्यू में बाजार की स्थितियों और मूल्य निर्धारण रुझानों के आधार पर अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए ग्रीन शू विकल्प है।

ii.SBI अपने वैश्विक कारोबार के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड जुटा रहा है।

iii.SBI ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वरिष्ठ असुरक्षित हरे फ्लोटिंग रेट नोट भी सफलतापूर्वक रखे हैं, जिन्हें 'ग्रीन नोट्स' के रूप में जाना जाता है, जो 29 दिसंबर 2028 को परिपक्व होते हैं।

SBI ने 5-वर्षीय वरिष्ठ असुरक्षित निश्चित दर नोटों के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए

SBI ने रेगुलेशन-S के तहत अर्ध-वार्षिक देय **5%** के कूपन पर 5 साल की परिपक्वता वाले वरिष्ठ असुरक्षित निश्चित दर नोटों के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। रेगुलेशन-S के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर होने वाली प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

- बॉन्ड 17 जनवरी, 2024 तक यूनाइटेड किंगडम (UK) में SBI लंदन शाखा के माध्यम से जारी किए जाएंगे और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में सूचीबद्ध किए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु:

i.यह धन उगाहना बैंक द्वारा 250 मिलियन अमरीकी डालर के वरिष्ठ असुरक्षित ग्रीन फ्लोटिंग रेट नोट्स, उर्फ "द ग्रीन नोट्स" के प्लेसमेंट के समापन पर है।

ii.29 दिसंबर, 2028 को परिपक्व होने वाला यह "ग्रीन नोट्स" जारी करना, SBI के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्यम अवधि के नोट कार्यक्रम का हिस्सा है और इसकी लंदन शाखा द्वारा संचालित एक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से आयोजित किया गया था।

- S&P द्वारा BBB- रेटिंग वाले ग्रीन नोट्स, SOFR (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) से 1.20% ऊपर फ्लोटिंग रेट के आधार पर जारी किए गए थे।

SBI ने ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए ग्रीन रुपी टर्म-डिपॉजिट FD योजना शुरू की

भारतीय स्टेट बैंक **(SBI)** ने पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं और पहलों के लिए धन जुटाने के लिए **SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट (SGRTD)** नामक एक विशेष सावधि जमा (FD) योजना शुरू की। SGRTD योजना निवासी व्यक्तियों, गैर-व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए खुली है।

- SGRTD योजना 3 अलग-अलग अवधि: 1,111 दिन, 1,777 दिन और 2,222 दिन प्रदान करती है। यह प्रारंभ में SBI के शाखा नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध है।
- SGRTD पर ब्याज दर संबंधित अवधि के लिए खुदरा और थोक डिपॉजिट्स के लिए कार्ड दर से 10 आधार अंक (BPS) कम होगी।
- वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक NRI वरिष्ठ नागरिक NRI स्टाफ को छोड़कर जनता के लिए लागू दर पर अतिरिक्त **ब्याज दर** के लिए पात्र हैं।

नोट: ग्रीन डिपॉजिट ब्याज वाली जमा राशि है, जो एक निश्चित अवधि के लिए एक विनियमित इकाई (RE) द्वारा प्राप्त की जाती है, और ग्रीन डिपॉजिट से निर्धारित आय विशेष रूप से ग्रीन फाइनेंस के लिए होती है।

PFC को गुजरात में पूर्ण स्वामित्व वाली फाइनेंस कंपनी स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी मिली

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (**PFC**), एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी **(GIFT-सिटी)** , गुजरात मेंइंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में पूर्ण स्वामित्व वाली फाइनेंस कंपनी स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (**RBI**) से मंजूरी मिल गई है।

- यह प्रतिष्ठान PFC के लिए नए व्यावसायिक अवसर खोलता है और भारत के पावर सेक्टर के वृद्धि में योगदान देता है।
- कहा जाता है कि GIFT सिटी प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल ऋण गतिविधियों और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
- PFC विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है।
- PFC RBI के साथ एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (SI-NBFC) के रूप में भी पंजीकृत है।

ISB में DLabs ने RBIH & UBI के साथ संयुक्त रूप से 'बिल्ड फॉर बिलियन्स' लॉन्च किया

हैदराबाद, तेलंगाना में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में DLabs ने **रिजर्व बैंक इनोवेशन हब** (RBIH) और **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** (UBI) के सहयोग से एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम "बिल्ड फॉर बिलियन्स" लॉन्च किया।

- यह वित्तीय सेवाओं और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर को संबोधित करके अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय समावेशन पर आधारित है।

प्रोग्राम के पीछे का कारण:

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व गिग श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और निर्माण मजदूरों द्वारा किया जाता है। उनकी चुनौतियों में कम और अस्थिर आय; अनियमित आय धाराएँ; ऋण और बचत तक सीमित पहुंच; और सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी शामिल है।

- अब, बिल्ड फॉर बिलियन प्रोग्राम इन मुद्दों के समाधान के लिए समर्पित फिनटेक स्टार्टअप का समर्थन करेगा।

एक्सेलरेटर प्रोग्राम में क्या है?

DLabs का यह **50-दिवसीय इक्विटी-फ्री एक्सेलेरेटर** व्यापक समर्थन प्रदान करता है, जिसमें परामर्श, क्षमता निर्माण, संसाधन, नेटवर्किंग के अवसर, बैंकों और निवेशकों को पिच करने का मौका और यूनियन बैंक के साथ एक अद्वितीय पायलटिंग अवसर शामिल है।

- DLabs, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) का एक बिजनेस इनक्यूबेटर, स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन, एक्सेलेरेशन और फंडिंग में माहिर है।

पात्रता:

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखने वाले स्टार्टअप 21 जनवरी, 2024 तक प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबमिशन अवधि के बाद, चयनित स्टार्टअप का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक के लिए अनुकूलित लक्ष्य निर्धारित होंगे।

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) के बारे में:

यह भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो वित्तीय क्षेत्र में इनोवेशन को एक्सेलरेट करने वाले वातावरण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

CEO– राजेश बंसल

मुख्यालय– बेंगलुरु, कर्नाटक

स्थापना – 2022

AIIB ने प्रोजेक्ट मेरिडियन के लिए SEIT में 486 करोड़ रुपये का निवेश किया

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक **(AIIB)** ने AIIB के प्रोजेक्ट **'इंडिया: प्रोजेक्ट मेरिडियन'** के लिए सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट **(SEIT)** में **486 करोड़ रुपये** (लगभग 58.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया है।

प्रमुख बिंदु:

i.SEIT भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट **(InvIT)** है।

ii. InvIT (SEIT) के पास भारत में देश भर में स्थित 1.54 गीगावाट-पीक कुल क्षमता की आठ ऑपरेटिंग सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्तियां हैं।

iii.SEIT की स्थापना महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड (MSPL) द्वारा की गई थी, जो महिंद्रा ग्रुप और ओंटारियो लिमिटेड (ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड (OTPPB) की 100% सहायक कंपनी) द्वारा समर्थित है।

iv.SEIT भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(SEBI)** InvIT विनियमों के तहत पंजीकृत है।

v.SEIT रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारत को अपने नेट ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है।

प्रोजेक्ट मेरिडियन के बारे में:

i.प्रोजेक्ट का उद्देश्य InvIT के रिन्यूएबल एनर्जी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को वित्तपोषित करके भारत में एक इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्ति वर्ग के रूप में InvIT के विकास का समर्थन करना है।

ii.प्रोजेक्ट की कुल फंडिंग **73 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है।

iii.AIIB की पर्यावरण और सामाजिक नीति **(ESP)** इस प्रोजेक्ट पर लागू होती है।

- इसमें पर्यावरण और सामाजिक बहिष्करण सूची और पर्यावरण और सामाजिक मानक शामिल हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

i.उपरोक्त फंडिंग भारत में InvITs में AIIB का दूसरा निवेश है।

ii. InvITs में पहला निवेश 2019 में प्रोजेक्ट इंडिया: OSE InvIT में किया गया था।

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के बारे में:

निदेशक मंडल के अध्यक्ष और अध्यक्ष - जिन लिकुन

मुख्यालय – बीजिंग, चीन

स्थापित – 2016

बैंक ऑफ बड़ौदा ने उच्च ब्याज दरों के साथ 'BoB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम' लॉन्च की

भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, **बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)** ने **बॉब 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम** नाम से एक विशेष रिटेल शार्ट-टर्म डिपाजिट स्कीम शुरू की। यह स्कीम निवासियों/अनिवासी साधारण (NRO) और निवासी वरिष्ठ नागरिकों को 360 दिनों के लिए डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर उच्च ब्याज दरें प्रदान करती है।

बॉब 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में:

i.यह 7.60% प्रति वर्ष (360 दिनों के लिए) तक की उच्च ब्याज दर प्रदान करता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.50% प्रति वर्ष शामिल है।

ii.ये दरें 2 करोड़ रुपये से कम की रिटेल डिपॉजिट्स पर लागू हैं और 15 जनवरी 2024 से प्रभावी हैं।

iii.यह स्कीम 1 वर्ष से कम परिपक्वता वाली डिपॉजिट्स पर उच्च रिटर्न चाहने वाले डेपोसिटर्स को पूरा करती है।

- बड़े बैंकों में, बॉब 360 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट्स (FD) के लिए सबसे आकर्षक दरों में से एक प्रदान करता है।

iv.भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिशानिर्देशों के अनुसार, यह स्कीम गैर-आवासीय बाहरी (NRE) डिपॉजिट्स के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रमुख विशेषताऐं:

i.ब्याज दरें: निवासियों/आम जनता और NRO के लिए 7.10% प्रति वर्ष और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60% प्रति वर्ष।

ii.यह स्कीम कॉलेबल डिपॉजिट्स (नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट्स लागू नहीं है) के लिए न्यूनतम जमा राशि **1,000 रुपये** (और आगे 1 रुपये के गुणकों में) और अधिकतम जमा राशि **2 करोड़ रुपये** तक की अनुमति देती है।

iii.डिपॉजिट की अवधि नामांकन के साथ 360 दिन है और एक ऑटो-नवीनीकरण सुविधा उपलब्ध होगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में:

MD और CEO– देबदत्त चंद

मुख्यालय– वडोदरा, गुजरात

स्थापित– 20 जुलाई 1908

टैगलाइन- इंडियास इंटरनेशनल बैंक

REC लिमिटेड ने JPY 61.1 बिलियन के कुल येन मूल्यवर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए

REC लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड), विद्युत मंत्रालय (**MoP**) के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम **(CPSE)** ने अपने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के **ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम** के तहत अपने उद्घाटन जापानी येन **(JPY)** 61.1 बिलियन मूल्य के ग्रीन बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किए हैं।

- यह किसी भी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (PSU) द्वारा जारी किया जाने वाला पहला येन ग्रीन बॉन्ड है।

निर्गमन के बारे में:

i.बॉन्ड क्रमशः 1.76%, 1.79% और 2.20% की उपज पर तीन अवधि अर्थात् 5-वर्ष, 5.25-वर्ष और 10-वर्ष में जारी किया जाता है।

ii.यह भारत से सबसे बड़ा येन-मूल्यवर्ग का निर्गम है और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अब तक का सबसे बड़ा यूरो-येन निर्गम है।

iii.बॉन्ड जारी करने से प्राप्त आय का उपयोग REC के ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बाहरी वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुरूप योग्य ग्रीन प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा।

यस बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेनदेन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया

यस बैंक लिमिटेड, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(RXIL)** की सहायक कंपनी, RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड **(RXIL ग्लोबल)** के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफार्म **(ITFS)** पर निर्यात फाइनेंस लेनदेन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

i.यह सहयोग भारतीय और ग्लोबल निर्यातकों और आयातकों दोनों को मंच के माध्यम से फैक्टरिंग, ज़ब्ती और अन्य ट्रेड फाइनेंश सर्विसेज जैसे प्रतिस्पर्धी फाइनेंसिंग ऑप्शन तक पहुंचने का अधिकार देता है।

ii.यह सहयोग भारत को ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस महाशक्ति बनाने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।

ITFS प्लेटफॉर्म के बारे में:

i.ITFS क्षेत्रीय और ग्लोबल स्तर पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी श्रृंखला के लिए एक फाइनेंसियल प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।

ii.यह प्लेटफॉर्म गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर **(IFSC)**, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT)-सिटी में स्थापित किया गया था।

यस बैंक ने वीफिन के सहयोग से MSME के लिए SmartFin लॉन्च किया

यस बैंक लिमिटेड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (**MSME**) की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित वीफिन सॉल्यूशंस लिमिटेड (**वीफिन**) द्वारा संचालित एंड-टू-एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस (**SCF**) प्लेटफॉर्म **SmartFin** लॉन्च किया है।

- SmartFin कॉर्पोरेट ग्राहकों के डीलरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए डिजिटल SCF ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है।

यस बैंक लिमिटेड के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) - प्रशांत कुमार
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापित – 2004
टैगलाइन - एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़

SBI लाइफ ने 'सरल स्वधन सुप्रीम' और 'स्मार्ट स्वधन सुप्रीम' लॉन्च किया

SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(SBI लाइफ)** ने दो नए उत्पाद **'SBI लाइफ - सरल स्वधन सुप्रीम'** और **'SBI लाइफ - स्मार्ट स्वधन सुप्रीम'** लॉन्च किए हैं।

- ये उत्पाद व्यक्तियों की इंश्योरेंस आवश्यकताओं और उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं।

विशेषताएँ:

i.प्रीमियम फ्लेक्सिबिलिटी - रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स या 7, 10, या 15 वर्षों की लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के विकल्प।
ii.फ्लेक्सिबल पॉलिसी टर्म- 10 से 30 वर्ष तक।
iii.मिनिमम इंश्योरेंस सम अश्योर्ड- दोनों पॉलिसियों के लिए 25 लाख रुपये।
iv.मैक्सिमम इंश्योरेंस सम अश्योर्ड- सरल स्वधन सुप्रीम के लिए मैक्सिमम सम 50 लाख रुपये तय की गई है, जबकि स्मार्ट स्वधन सुप्रीम के लिए मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
v.आयु मानदंड -

SBI लाइफ - सरल स्वधन सुप्रीम

मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम (मैक्स) **50** वर्ष की आयु वाला व्यक्ति इंश्योरेंस उत्पाद के लिए नामांकन कर सकता है। और इसकी मैच्योरिटी के लिए मैक्सिमम उम्र **65** साल होगी।

SBI लाइफ - स्मार्ट स्वधन सुप्रीम

मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु **60** वर्ष वाला व्यक्ति इंश्योरेंस उत्पाद के लिए नामांकन कर सकता है। और इसकी मैच्योरिटी की मैक्सिमम आयु **75** वर्ष होगी।

प्रमुख बिंदु:

i.पॉलिसीधारकों को मैच्योरिटी पर भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 100% (अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर) प्राप्त होता है।
ii.ये प्लान्स पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर एकमुश्त लाभ भी प्रदान करती हैं।
iii.ये प्लान्स प्रीमियम पेमेंट टर्म , पॉलिसी ड्यूरेशन, प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी आदि चुनने की सुविधा प्रदान करती हैं।
iv.पॉलिसीधारक आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रचलित मानदंडों के अनुसार कर लाभ के लिए पात्र हैं।

SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) – अमित झिंगरन
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
शामिल– 2000